आज का विचार
जिसे बुरा लग जाए वह मित्र नहीं, और जिसे बुरा न लगे, उसके जैसा कोई मित्र नहीं।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का

3

सिटी दर्पण-राष्ट्रीय दैनिक हिंदी समाचार पत्र की अधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए स्कैन करें।

चंडीगढ़ । मंगलवार, 17 मार्च, 2026 | वर्ष 24, अंक 66, मूल्यः 3 रुपए, पृष्ठ 8 | RNI Regn No.: CHAHIN/2003/09265 Established 2003 | www.citydarpan.com

आप सरकार की काम करने की राजनीति ने सिर्फ चार सालों में सभी गारंटियां पूरी की: भगवंत सिंह मान

लोगों ने कांग्रेस, अकाली और भाजपा को ठुकराकर हम पर भरोसा जताया था, हमने लोगों का विश्वास नहीं टूटने दिया

यज्ञांश शर्मा
चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी की सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि उनकी सरकार ने काम की राजनीति के रास्ते लोगों को दी गई सभी गारंटियां पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा को ठुकराकर हम पर उम्मीदें लगाई थी और हमने लोगों का भरोसा नहीं टूटने दिया। मुख्यमंत्री ने मुख्य उपलब्धियों का जिक्र किया, जिनमें मुफ्त बिजली, किसानों के लिए दिन में बिजली, 78 प्रतिशत खेतों को नहरी पानी, 65,000 सरकारी नौकरियां और 5.5 लाख रोजगार के नए मौके, आम आदमी क्लिनिकों के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज शामिल हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की नशा विरोधी अभियान युद्ध नशे के विरुद्ध, 1.55 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश और सड़क सुरक्षा फोर्स के साथ सरकार के इरादे स्पष्ट हैं कि पंजाब के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जहां कांग्रेस, अकाली और भाजपा सत्ता की चिंता कर रहे हैं, वहीं 'आप' सरकार पंजाब को बचाने के लिए फिक्रमंद है और राज्य में फूट डालो राजनीति को सफल नहीं होने देगी।

'आप' सरकार के चार साल पूरे होने पर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार ने चार सालों में सभी वादे पूरे करके राजनीति में नई परंपरा कायम की है, जबकि पारंपरिक पार्टियां पांच सालों में भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा, साल 2022 में शहीद-ए-आजम भगत सिंह के पैतृक गांव में पदभार संभालने के बाद, पंजाब सरकार ने कई लोक-हितैषी फैसले लिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, मेरे साथ, लाखों पंजाबियों ने राज्य की पुरानी शान बहाल करने की शपथ ली थी।

अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पिछले चार सालों में,

पंजाब सरकार ने लोगों की भलाई के लिए अथक मेहनत और समर्पण भावना से प्रयास किए हैं और उनके साथ किए वादे पूरे कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा, आने वाला साल पंजाब को विकास और खुशहाली के एक नए शिखर पर ले जाने के लिए समर्पित होगा।

शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, भारत सरकार के सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब के सरकारी स्कूल अब पढ़ाई में देश में पहले स्थान पर हैं। उन्होंने आगे कहा, सरकारी स्कूलों में अब कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठता क्योंकि एक लाख से अधिक डेस्क दिए गए हैं ताकि हर विद्यार्थी सम्मान से पढ़ सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्रांति के तहत 9,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम और 5,000 कंप्यूटर लैब खोले गए हैं, जिससे पूरे पंजाब के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा मिल रही है। उन्होंने आगे कहा, पंजाब के इतिहास में पहली बार ठेके पर रखे शिक्षकों को नियमित नौकरियां दी गई हैं और सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षक फिनलैंड, सिंगापुर और आई.आई.एम. अहमदाबाद में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिससे पंजाब में बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही है। उन्होंने आगे कहा, पंजाब के युवाओं को नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि नौकरियां पैदा करने वाले बनने के लिए तैयार किया जा रहा है और हर साल लगभग 1.5 लाख कॉलेज विद्यार्थी उद्यमिता और कौशल सीख रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, सरकारी स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ साल 2026 में सरकारी स्कूलों के 305 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. मेन्स और 845 ने नीट पास की।

स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को बड़े प्राइवेट अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। उन्होंने आगे कहा, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, जब पिछली सरकारों ने 75 सालों में पंजाब में सिर्फ 400 क्लीनिक बनाए थे, वहीं पंजाब सरकार ने पिछले चार सालों में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं। उन्होंने आगे कहा, इन क्लीनिकों की ओ.पी.डी. में इलाज के लिए आने वालों की संख्या पांच करोड़ से अधिक हो गई है।

कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में आग, 10 मरीजों की मौत

अग्निकांड पर प्रधानमंत्री ने जताया शोक, मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोषसेअनुग्रह राशि की घोंषणा

एजेंसी (हि.स.)
भुवनेश्वर

ओडिशा के कटक स्थित श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ट्रॉमा केयर इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) में सोमवार तड़के भीषण आग लगने से कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई। इस हादसे से अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और गंभीर मरीजों को तुरंत अन्य वार्डों में स्थानांतरित किया गया। आग सुबह करीब 2:30 से 3:00 बजे के बीच इमरजेंसी विभाग की पहली मंजिल पर स्थित ट्रॉमा आईसीयू में लगी, जहां उस समय 23 मरीज भर्ती थे। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद होगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।

मृतकों की पहचान रमेश परिडा, दशारू मुंडा, एम.डी. न्युम, गौरांग बारिक, एस.के. अब्दुल सत्तार, मधुसूदन दलाई, कृष्णचंद्र बिस्वाल, रवींद्र दास, चारू परिडा और मेनका राउत के रूप में हुई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अन्य मरीजों को सुरक्षित रूप से

अस्पताल के विभिन्न विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है और उनका उपचार जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग भी मौजूद थे।

दोनों नेताओं ने अस्पताल के प्रभावित हिस्से का निरीक्षण किया और अन्य वार्डों में इलाज करा रहे मरीजों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्थानांतरित किए गए सभी मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए और उनके उपचार में किसी प्रकार की बाधा न आए।

मुख्यमंत्री ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच में यह भी देखा जाएगा कि अस्पताल में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी तो नहीं थी।

मुख्यमंत्री ने अग्निशमन सेवा के महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से एससीबी मेडिकल कॉलेज में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करें और अस्पताल को जल्द से जल्द पूरी तरह फायर-कम्प्लायंट बनाया जाए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि घायल और अन्य स्थानांतरित मरीजों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही ओडिशा के सभी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दे चुकी है। इसके लिए चालू बजट में 320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इस दिशा में काम जारी है। साथ ही आगामी बजट में अग्नि सुरक्षा ढांचे को और मजबूत करने के लिए 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान करने की योजना है।

इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से फोन पर बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, मरीजों के स्थानांतरण और उन्हें दी जा रही विशेष चिकित्सा सुविधाओं के बारे में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को घटना की जांच के लिए आदेशित उच्च स्तरीय जांच के बारे में भी जानकारी दी।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह घटना बेहद पीड़ादायक है और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोदिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से आर्थिक सहायता की भी घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा और स्थानीय प्रशासन सहित विभिन्न विभाग मिलकर स्थिति को संभालने और प्रभावित मरीजों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए समन्वय के साथ काम कर रहे हैं।

हरियाणा में राज्य सभा की दो सीटों के लिए 88 विधायकों ने किया मतदान

एजेंसी (हि.स.)
चंडीगढ़

हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए सोमवार हुए मतदान के दौरान कुल 90 में से 88 विधायकों ने वोट डाले। दो विधायकों वाली इंडियन नेशनल लोकदल ने अंतिम समय में चुनाव के बहिष्कार का ऐलान करते हुए वोट नहीं डाला। हरियाणा के चुनावी रण में भाजपा के संजय भाटिया, कांग्रेस के कर्मवीर बोद्ध तथा निर्दलीय सतीश नांदल चुनाव मैदान में हैं।

विधायकों की संख्या के अनुसार प्रथम वरियता के आधार पर संजय भाटिया राज्य सभा में पहुंच गए हैं। दूसरी सीट के लिए दो उम्मीदवार मैदान में होने के कारण मतदान हुआ है। शाम चार बजे मतदान प्रक्रिया पूरी होने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने टोहाना से कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह तथा ऐलनाबाद विधायक भरत सिंह बैनीवाल पर वोट की गोपनियता भंग करने का आरोप लगाते हुए आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज की वोट पर आपत्ति जताई। चुनाव अधिकारी ने तीनों शिकायतें केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दी। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा इस पर निर्णय लिए जाने के बाद ही मतगणना होगी। रात नौ बजे तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं आने के कारण मतगणना अटकी हुई थी।

सोमवार को राज्य सभा के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी विधानसभा पहुंचे और वोट डाला। सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव, श्रुति चौधरी, अरविंद शर्मा, कृष्ण लाल पंवार ने भी राज्य सभा के लिए वोट किया।

हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज दोनो पैरों में फ्रेक्चर के चलते व्हील चेयर पर वोट डालने के लिए पहुंचे। पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास बीमारी के चलते अपने दो सहयोगियों के साथ विधानसभा में वोट डालने के लिए पहुंचे। सुबह नौ बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होने के बाद 11.15 बजे तक 25 विधायकों ने तथा 12.15 तक 40 विधायकों ने वोट डाला। बाद दोपहर 2.50 बजे तक कुल 90 में से 87 विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण माता का निधन होने के कारण आज अस्थी विसर्जन के लिए हरिद्वार गए थे। जिसके चलते वह करीब तीन बजे विधानसभा में पहुंचे और सबसे अंत में उन्होंने अपना वोट डाला। भिवानी से भाजपा विधायक घनश्याम सराफ की राज्यसभा की वोट भाजपा नेता वीरेंद्र गर्ग ने पोल की। घनश्याम सराफ बीमार हैं। राज्यसभा के चुनाव में यह नियम है कि किसी उम्मीदवार की सहमति से उनका नामित सहयोगी वोट डाल सकता है। इसी के चलते वीरेंद्र गर्ग ने आज यह वोट पोल की।

साहित्य अकादमी पुरस्कार-2025 की घोषणा, 24 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियां सम्मानित, 31 मार्च को होगा सम्मान समारोह

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

साहित्य अकादमी ने वर्ष 2025 के लिए अपने प्रतिष्ठित वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार देश की 24 भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को सम्मान के लिए चुना गया है। अकादमी की सचिव पल्लवी प्रशांत होल्कर की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, चयनित कृतियों में कविता, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा और संस्मरण जैसी विभिन्न

विधाओं की पुस्तकें शामिल हैं। कुल मिलाकर इस वर्ष 8 कविता-संग्रह, 4 उपन्यास, 6 कहानी-संग्रह, 2 निबंध, 1 साहित्यिक आलोचना, 1 आत्मकथा और 2 संस्मरण को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन पुरस्कारों का चयन 24 भारतीय भाषाओं की अलग-अलग निर्णायक समितियों (ज्यूरी) की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक विजेता को उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी। सम्मान समारोह 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कविता श्रेणी में बांग्ला की 'श्रेष्ठ कबिता', डोगरी की 'ठाकुर' सतसई, गुजराती की 'भट्टखडकी', कश्मीरी की 'नजदावनेकी पॉट अलाव', ओड़िया की 'पदपुराण', संस्कृत की 'प्रस्थानचतुष्टये ब्रह्मघोषः', तेलुगु की 'अनिमेष' और उर्दू की 'सफर जारी है' को सम्मानित किया जाएगा। इन कृतियों के माध्यम से भारतीय भाषाओं की काव्य परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और समकालीन संवेदनाओं को प्रभावी रूप से अभिव्यक्ति मिली है।

उपन्यास विधा में असमिया लेखक देवब्रत दास की 'कड़ि खेलर साधु', बोडो भाषा की 'दोनै लामाः मोनसे गाथोन (सहायसुलि ब्रह्म)', अंग्रेजी उपन्यास 'क्रिमसन स्प्रिंग' (नवतेज सरना) और मलयालम की 'मायामानुश्यर' (एन. प्रभाकरन) को पुरस्कार के लिए चुना गया है।

सर्वदलीय बैठक में आठ सांसदों के निलंबन को वापस लेने पर सहमति

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में आठ निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लेने पर सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार इन सांसदों का निलंबन मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद औपचारिक रूप से वापस लिया जाएगा। जिन सांसदों का निलंबन वापस लिया जाएगा उनमें गुरजीत सिंह औजला, हिबी ईडन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, अमरींदर सिंह राजा वारिंग, बी. मणिकम टैगोर, डॉ. प्रशांत यदोराव पाडोले, चामला किरण कुमार रेड्डी और एस.

वेंकटेशन शामिल हैं। इन सांसदों को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव के आधार पर तीन फरवरी से शुरू हुए सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेताओं ने संसद की गरिमा और स्थापित परंपराओं को बनाए रखने पर भी सहमति जताई। इसके तहत यह तय किया गया कि कोई भी सदस्य सदन के वेल में दूसरी ओर नहीं जाएगा, कागज फाड़कर आसन की ओर नहीं फेंकेगा और न ही अधिकारियों की मेज पर चढ़ेगा। इसके अलावा, सभी सदस्य सदन की मयार्दा का पालन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा न हों। इस बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसदों को संसद परिसर में मयार्दा बनाए रखने के संबंध में एक बुलेटिन भी जारी किया है। बुलेटिन में दिशानिर्देश 124अ(2)(८) का हवाला देते हुए कहा गया है कि संसद परिसर के क्षेत्र और मार्ग को सांसदों के लिए खुला और बाधारहित बनाए रखना आवश्यक है। बुलेटिन में स्पष्ट किया गया कि संसद परिसर में हथियार, झंडे, पोस्टर, लाठी, भाला, तलवार, डंडे और ईंट आदि ले जाना निषिद्ध है। सांसदों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पोस्टर, प्लेकार्ड या बैनर न लाएं और न ही उनका प्रदर्शन करें।

देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं भारत के युवा : ज्योतिरादित्य सिंधिया

एजेंसी (हि.स.)
गुना

केंद्रीय संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि विद्यार्थी नवाचार, कौशल विकास तथा रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। भारत के युवा देश के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और एफडीडीआई जैसे संस्थान उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहे हैं।

केन्द्रीय मंत्री सिंधिया सोमवार को मध्य प्रदेश के गुना स्थित डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई), परिसर के भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर संस्थान की शैक्षणिक एवं तकनीकी सुविधाओं का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों, संकाय सदस्यों और अधिकारियों के साथ संवाद किया। सिंधिया ने संस्थान की विभिन्न प्रयोगशालाओं का भी निरीक्षण किया, जिनमें डिजाइनिंग, कटिंग, क्लोजिंग, कंपोनेंट तथा लास्टिंग लैब शामिल हैं। इस दौरान विद्यार्थियों ने फुटवियर डिजाइन और उत्पादन से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रदर्शन भी किया।विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने उन्हें नवाचार, कौशल विकास तथा रचनात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवा साथियों से आग्रह किया कि आप केवल नौकरी खोजने वाले नहीं, बल्कि जॉब क्रियेटर्स बनने का संकल्प लें और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया एवं लोकल टू ग्लोबल के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में अपनी भूमिका निभाएँ। एफडीडीआई के प्रबंध निदेशक विवेक शर्मा (आईआरएस) ने बताया कि एफडीडीआई देश के फुटवियर, फैशन, लेदर तथा रिटेल उद्योगों के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

रहा है। कार्यकारी निदेशक मंजु मन ने अपने धन्यवाद ज्ञापन में बताया कि एफडीडीआई गुना परिसर का उद्घाटन वर्ष 2017 में सिंधिया द्वारा किया गया था, जब वे भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में यह परिसर क्षेत्र में डिजाइन तथा कौशल विकास के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया एफडीडीआई गुना परिसर में बी.डेसझ्र फुटवियर डिजाइन एंड प्रोडक्शन, बी.डेसझ्रफैशन डिजाइन, एमबीएझ्ररिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को डिजाइन, तकनीक तथा प्रबंधन के क्षेत्रों में समग्र ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे वे तेजी से विकसित हो रहे फुटवियर, फैशन और रिटेल उद्योग में सफलतापूर्वक अपना योगदान दे सकें।

केंद्र प्रभारी जितेंद्र गुप्त ने जानकारी दी है कि संस्थान में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट गतिविधियाँ प्रारम्भ हो चुकी हैं। इस वर्ष अब तक एफडीडीआई के 12 परिसरों में आयोजित प्लेसमेंट प्रक्रिया में अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। एफडीडीआई गुना परिसर के विद्यार्थियों का चयन भी प्रतिष्ठित ब्रांड्स जैसे मेट्रो, हाउस ऑफ रेयर, जे-क्यू-आर स्पोर्ट्स तथा डेंड्राइट में हो चुका है, जबकि शेष विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट प्रक्रिया जारी है। इस अवसर पर एफडीडीआई गुना एवं नोएडा की कार्यकारी निदेशक मंजू ह्यमनह्ल ने संस्थान की गतिविधियों, अधोसंरचना तथा कौशल विकास से जुड़े प्रयासों पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को केन्द्रीय मंत्री सिंधिया के साथ संवाद किया, जिसमें उन्होंने अपने करियर, कौशल विकास तथा उद्योग से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। साथ ही मेधावी छात्रों को केन्द्रीय मंत्री सिंधिया ने सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में कार्यकारी निदेशक ने धन्यवाद दिया और केन्द्रीय मंत्री सिंधिया का संस्थान के विद्यार्थियों को प्रेरित करने तथा परिसर का दौरा करने के लिए आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेन्द्र सिकरवार, पूर्व मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सारिका लुंबा, सांसद प्रतिनिधि हरिसिंह यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का किया उद्घाटन

कहा, ट्यूलिप गार्डन कश्मीर के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक

एजेंसी (हि.स.)
श्रीनगर

कश्मीर में वसंत ऋतु के आगमन पर एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सोमवार को आम जनता के लिए खोल दिया गया। इस बहुप्रतीक्षित पुष्प उद्यान को देखने के लिए हजारों पर्यटकों और स्थानीय लोगों के आने की उम्मीद है।

श्रीनगर में जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। ट्यूलिप गार्डन का खुलना घाटी में वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है और कश्मीर के पर्यटन सीजन की शुरूआत का संकेत देता है। प्रसिद्ध डल झील के नजारे वाले सीढ़ीदार ढलानों पर फैला यह उद्यान विभिन्न रंगों और किस्मों के लाखों ट्यूलिप से खिल उठेगा, जो आगंतुकों को एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष उद्यान में ट्यूलिप की 70 से अधिक किस्में लगाई गई हैं। ट्यूलिप के अलावा हयासिंथ, डैफोडिल, मस्करी और रैननकुलस जैसे अन्य बसंत के फूल भी लगाए गए हैं, ताकि बगीचे की सुंदरता बढ़े और फूलों की विविधता में और इजाफा हो। हर साल यह बगीचा फूलों के मौसम में देश और विदेश से हजारों पर्यटकों, प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों को आकर्षित करता है, जिससे यह बसंत ऋतु में कश्मीर के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बन जाता है। अधिकारियों ने फूलों के मौसम में आने वाली संभावित भीड़ को संभालने के लिए परिवहन सुविधाएं, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा तैनाती और अन्य आवश्यक पर्यटक सुविधाओं सहित व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।

मुख्यमंत्री उमर ने एलपीजी, पेट्रोल और आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की स्थिति की समीक्षा की

श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आगामी ईद और नवरात्रि के त्योहारों और पश्चिम एशिया की मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों के स्टॉक की स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री सकीना इटू और सतीश शर्मा, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, प्रधान सचिव गृह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के आयुक्त सचिव, सूचना आयुक्त सचिव, विभागों के प्रमुख, सभी जिलों के उपायुक्त, सूचना निदेशक, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक आशुतोष गुप्ता, तेल कंपनियों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बाहर से आए अधिकारियों ने ऑनलाइन माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में पेट्रोलियम उत्पादों, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन को सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए ताकि किसी भी जिले में कृत्रिम कमी, जमाखोरी या कालाबाजारी न होने दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे लगता है कि पूरा प्रशासन स्थिति से भलीभांति अवगत है और स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं बस इतना दोहराना चाहूंगा कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन जिलों में भी इसका समर्थन और सहयोग आवश्यक है। उन्होंने सभी उपायुक्तों को आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।

आपदा से निपटने को हर जिले में खुलेंगे राज्य आपदा रिलीफ स्टोर : डीजी अटवाल

- 70 हजार लोगों को सिविल डिफेंस सेवाओं के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार हर जिले में स्टेट डिजास्टर रिलीफ स्टोर (एसडीआरएस) स्थापित करेगी। इन स्टोरों में आपदा के समय प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहेगी। साथ ही राज्य में 70 हजार लोगों को सिविल डिफेंस सेवाओं के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

यह जानकारी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) की महानिदेशक आईपीएस सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने दी। वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र खनियारा, धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित कर रही थीं। सम्मेलन का विषय कंटेम्परेरी इश्यू एंड चैलेंजेज इन डिजास्टर मैनेजमेंट था। कार्यक्रम में एचपीयू के कुलपति प्रो. महावीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डीजी एसडीआरएफ सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने बताया कि हर जिले में स्थापित होने वाले एसडीआरएस में आपदा की स्थिति में डिग्निटी किट उपलब्ध कराई जाएगी। इन किटों में भोजन, पानी, गर्म कपड़े, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल होगी, ताकि प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में 32 प्रतिशत लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर की जानकारी नहीं है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 37 प्रतिशत तक है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। शिमला और धर्मशाला जैसे क्षेत्रों में समय से पहले गर्मी पड़ रही है, जिसका असर खेती और बागवानी पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में पहले लगातार बारिश होती थी, लेकिन अब अत्यधिक भीड़ और पर्यावरणीय दबाव के कारण नई समस्याएं सामने आ रही हैं। इससे राज्य को हर साल करोड़ों रुपये का नुकसान और जनहानि भी झेलनी पड़ रही है। सतवंत अटवाल त्रिवेदी ने कहा कि राज्य में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में आपदा के दौरान एसडीआरएफ और पुलिस के जवान 52 दिन तक थुनाग क्षेत्र में लगातार तैनात रहे, जहां हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे।

डमटाल में 114 ग्राम चरस बरामद दो आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस जिला नूरपुर की सीआईए टीम ने डमटाल पुलिस थाना के तहत एक्साइज बैरियर के पास दो लोगों से 114.2 ग्राम चरस बरामद की है। मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस जिला नूरपुर के तहत पुलिस टीमें गश्त व नशा विरोधी अभियान के दौरान क्षेत्र कंडवाल, भदरोया, डमटाल व छन्नी आदि में मौजूद थी। इसी दौरान पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एनएच-44 के पास एक्साइज बैरियर भदरोया के समीप सड़क किनारे दो लोग बैठे हुए हैं तथा उनके पास एक कैरी बैग में भारी मात्रा में चरस मौजूद है और वे इसे बेचने की फिराक में हैं। सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी जहां पर दो संदिग्ध व्यक्ति बैठे हुए पाए गए। पूछताछ करने पर उन्होंने अपनी पहचान बलदेव पुत्र नन्दलाल निवासी गांव मकण, डाकघर सनवाल, तहसील चुराह जिला चम्बा (उम्र 44 वर्ष) तथा जीत पुत्र लोभी निवासी गांव मकण, डाकघर सनवाल, तहसील चुराह जिला चम्बा (उम्र 40 वर्ष) के रूप में बताई। पुलिस ने जब उनके कैरी बैग की तलाशी ली तो बैग के भीतर पोलिथीन में छिपाकर रखी 114.2 ग्राम चरस बरामद हुई। इस संबंध में पुलिस थाना डमटाल में आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है तथा आगे की जांच जारी है।

पीएमईजीपी और जेकेआरईजीपी योजनाओं की प्रगति की डीसी कठुआ ने की समीक्षा

कठुआ। उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा ने सोमवार को डीसी कार्यालय परिसर में बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और जम्मू-कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिले में हो रही प्रगति की समीक्षा की। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक मुश्ताक चैधरी, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अमन जसरोटिया, आरसेटी कठुआ की निदेशक उत्पला सैकिया, केवीआईबी के जिला अधिकारी सुरिंदर शर्मा और आईपीओ डीआईसी शिवांग गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपायुक्त ने दोनों स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्वीकृत, अनुमोदित और लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि कुछ मामलों को दस्तावेजों की कमी और तकनीकी कारणों से बैंकों द्वारा अस्वीकृत किया गया है, जबकि कुछ पात्र मामले अभी भी विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। उपायुक्त ने बैंकों और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि लंबित पात्र मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। उन्होंने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को यह भी निर्देश दिया कि अस्वीकृत मामलों का विवरण संबंधित विभागों को भेजा जाए।

जयराम सरकार में आए 92 हजार 439 करोड़ के निवेश को कांग्रेस ने रोका : भाजपा

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में निवेश और विकास के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा शासन में आये 92 हजार करोड़ के निवेश को धरातल पर उतरने से रोकने का आरोप लगाया है।

त्रिलोक कपूर ने सोमवार को कहा कि यदि प्रदेश में विकास कार्यों और निवेश की बात की जाए तो 2017 से 2022 तक जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। उन्होंने दावा किया कि उस समय प्रदेश में औद्योगिक विकास, पर्यटन, आईटी, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में आयोजित राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट को प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी निवेश पहल माना गया था। इस दौरान कुल 603 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें लगभग 92 हजार 439 करोड़ रुपये के संभावित निवेश का अनुमान लगाया गया था।

इन समझौतों में एग्रीबिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी, सिविल एविएशन, हाइड्रो और नवीकरणीय ऊर्जा, वेलनेस एवं आयुष, हाउसिंग और शहरी विकास तथा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आठ प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया था। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि आईटी सेक्टर में भी उस समय 14 एमओयू किए गए थे, जिनकी अनुमानित निवेश राशि करीब 2,833 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा वर्ष 2019 की पर्यटन नीति के तहत होटल परियोजनाओं, वेलनेस सेंटर और केबल कार परियोजनाओं के लिए भी कई निवेश प्रस्ताव आए थे। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोलन जिले के नालागढ़ में स्थापित किए जाने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए उद्योग विभाग ने करीब 810 करोड़ रुपये के 15 एमओयू किए थे। उनका कहना है कि इससे प्रदेश में फार्मा और मेडिकल उपकरण उद्योग को बढ़ावा मिलने की संभावना थी। त्रिलोक कपूर ने यह भी कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2021-22 के दौरान छह एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, जिनकी अनुमानित निवेश राशि एक हजार करोड़ रुपये से अधिक थी।

संक्षिप्त-समाचार

आम आदमी पार्टी का हिमाचल की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और इसके लिए संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिससे संगठन को और सक्रिय बनाया जा सके। पार्टी के हिमाचल प्रभारी ऋतुराज झा के नेतृत्व में पिछले करीब दस महीनों से प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान कई स्थानों पर ब्लॉक स्तर तक कमेटियों का गठन भी किया गया है। पार्टी का कहना है कि आगामी चुनावों से पहले प्रदेशभर में संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सोमवार को शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान हमीरपुर से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जगत राम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता लंबे समय से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से परेशान है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में एक तीसरे राजनीतिक विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रही है।

नाहन में 18 मार्च को वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित होगा स्वास्थ्य जांच शिविर

नाहन। जिला प्रशासन सिरमौर तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के सहयोग से 18 मार्च को राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्मृति क्षीणता (डिमेंशिया स्क्रीनिंग) एवं सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने बताया कि यह शिविर आस्था डे-केयर सेन्टर, पक्का टैंक के नजदीक आयोजित किया जायेगा जिसमें 60 वर्ष व इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक भाग ले सकते है। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य जांच,स्मृति क्षीणता (डिमेंशिया स्क्रीनिंग) शिविर डा0 वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में आयोजन किया जायेगा। इस शिविर में वरिष्ठ नागरिकों की स्मृति क्षीणता, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श तथा आवश्यक चिकित्सा मार्गदर्शन निशुल्क प्रदान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की स्मृति संबंधी समस्याओ की समय रहते पहचान कर उचित उपचार एवं मार्ग दर्षन उपलब्ध करवाना हैं जिससें उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर हो सके।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बचाने के लिए पीएम-राहत योजना शुरू की

जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम-सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार (पीएम-राहत) योजना शुरू की है। परिवहन विभाग से इस संबंध में प्राप्त एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल महत्वपूर्ण ₹गोल्डन आवर₹ के दौरान 140 से अधिक नामित अस्पतालों में प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज सुनिश्चित करती है जो दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों तक कवर करती है जिससे तत्काल चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित होती है और जीवित रहने की संभावना में काफी सुधार होता है। परिवहन, स्वास्थ्य, पुलिस और जिला प्रशासन सहित सभी संबंधित विभाग सड़क दुर्घटनाओं के मामले में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के अलावा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निकट समन्वय में काम करेंगे। सरकार ने जनता से सड़क दुर्घटनाओं की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या नियंत्रण कक्ष को देने का आग्रह किया है जिससे पीड़ितों को शीघ्रता से नामित अस्पतालों तक पहुंचने में मदद मिलेगी ताकि योजना के तहत समय पर उपचार प्रदान किया जा सके।

नूरपुर में लापता व्यक्ति का पेड़ से लटका मिला शव, आत्महत्या का मामला दर्ज

धर्मशाला। पुलिस थाना नूरपुर में बीते दिन दर्ज युवक की गुमशुदगी के मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद उक्त युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। गौरतलब है कि बीते दिन केवल कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी वार्ड नम्बर 3 नूरपुर, जिला कांगड़ा (आयु लगभग 35 वर्ष) के संबंध में परिजनों ने पुलिस थाना नूरपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त जब तलाश शुरू की तो उक्त व्यक्ति का शव डिफेंस रोड, जब्बर खड्ड के पास पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस थाना नूरपुर की टीम मौके पर पहुंची तथा फोरेंसिक की टीम को भी सूचित किया गया, जिन्होंने मौके का निरीक्षण किया। एसपी नूरपुर कुलभूषण वर्मा ने बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। परिजनों के बयान दर्ज किए गए, जिनके अनुसार मृतक का अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान था। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि मृतक ने पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या की है। मामले में कोई संदिग्ध परिस्थिति या आपराधिक तत्व सामने नहीं आया है। मृतक का पोस्टमार्टम सिविल अस्पताल नूरपुर में करवाया गया। आवश्यक कानूनी कार्यवाही पूर्ण करते हुए बीएनएसएस की धारा 194 के तहत कार्यवाही की गई। पोस्टमार्टम के उपरांत शव को अंतिम संस्कार हेतु मृतक के भाई सुनील कुमार को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है।

दैनिक सिटी दर्पण
आईना सच का
न्वोन्मेषकः स्व. कृष्णा शर्मा
स्व. गीता शर्मा
संस्थापकः स्व. सतपॉल शर्मा
स्वामी, प्रकाशक मुद्रक एवं संपादक भूपिंद्र शर्मा द्वारा इंप्रेशन्ज प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं. 22, ग्राउंड फ्लोर, फेस-2, इंडस्ट्रियल एरिया, पंचकूला-134113 (हरियाणा) पर मुद्रित एवं 801/1, सेक्टर 40ए, चंडीगढ़ से प्रकाशित-160036
सभी विवादों का केंद्र न्यायालय चंडीगढ़ होगा।
स्थानीय कार्यालय
801/1, सेक्टर-40ए, चंडीगढ़।
संपर्कः 7888450261
Email: citydarpan1@gmail.com

चंदवां में 1.3 करोड़ का आयुष्मान आरोग्य मंदिर समर्पित, 25 लाख के विकास कार्यों की शुरूआत

एजेंसी (हि.स.)
कठुआ

जसरोटा के विधायक राजीव जसरोटिया ने सोमवार को पंचायत चंदवां के ठाकुरपुरा में करीब 1.3 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण किया। इस आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र से चंदवां सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, मातृ-शिशु देखभाल और बेसिक जांच सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी।

इस अवसर पर विधायक जसरोटया ने पंचायत चंदवां में करीब 25 लाख रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया। इन कार्यों में क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए दो नए ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा तीन लेन ड्रेन और सार्वजनिक प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है, जिससे स्थानीय लोगों को लंबे समय से चली आ रही बिजली व जल निकासी की समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जसरोटिया ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उनके घर के नजदीक उपलब्ध कराएगा और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भी जागरूकता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, बिजली, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, ताकि गांवों को भी शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकें। साथ ही नए ट्रांसफार्मर लगने से बिजली आपूर्ति स्थिर होगी और वोल्टेज की समस्या में कमी आएगी। इस दौरान विधायक ने स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र के विकास और जनकल्याण के लिए आने वाले समय में और भी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। जनगणना-2027 की तैयारी तेज, कठुआ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू।

विधायक केवल पठानिया ने धारकंडी क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगातें

धर्मशाला। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने सोमवार को धारकण्डी क्षेत्र में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर क्षेत्र के विकास को नई गति प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कुल 22.35 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने 16.43 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कनोल-लग बतूनी-मोर्छ सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। लगभग 10 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण से क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने भनाला से रूलेड सड़क पर 1.91 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 30 मीटर लंबे पुल का शिलान्यास किया। वहीं, 3.74 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित ब्रहाल पुल पर बने 50 मीटर लंबे पुल का लोकार्पण भी किया। इसी क्रम में केवल सिंह पठानिया ने 27.41 लाख रुपये की लागत से बने 25 केवीए विद्युत वितरण उपकेंद्र, लग बतूनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस उपकेंद्र के शुरू होने से क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी तथा लोगों को बिजली संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी।

महानिदेशक जेल ने किया जिला कारागार धर्मशाला का निरीक्षण

एजेंसी (हि.स.)
धर्मशाला

महानिदेशक कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं हिमाचल प्रदेश अभिषेक त्रिवेदी ने सोमवार को लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह कारागार धर्मशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कारागार में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा सुधारात्मक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की।

महानिदेशक ने कारागार परिसर का निरीक्षण करते हुए वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा कैदियों के पुनर्वास और सुधार से जुड़ी गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कारागार में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान महानिदेशक ने कैदियों से भी बातचीत की तथा उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैदियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए और उन्हें सुधारात्मक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जोड़ा जाए ताकि वे समाज की मुख्यधारा में पुनः स्थापित हो सकें। इस अवसर पर हिमकारा योजना के बारे में जिला जन संपर्क अधिकारी धर्मशाला द्वारा तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की गई, जिसमें कारागार में चल रही विभिन्न गतिविधियों और सुधारात्मक प्रयासों को दशार्या गया।

निरीक्षण के दौरान उनके साथ डीआईजी उत्तरी रेंज सोम्या सांबशिवन तथा अधीक्षक कारागार धर्मशाला विकास भटनागर भी उपस्थित रहे।

बल्ह में सड़क, पानी और सिंचाई की समस्याओं से जनता परेशान, सरकार पर उठे सवाल : गांधी

एजेंसी (हि.स.)
मंडी

मंडी जिला के बल्ह विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र सिंह गांधी ने क्षेत्र की विभिन्न विकास समस्याओं को लेकर उपायुक्त मंडी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई योजनाओं और अधूरे सरकारी भवनों के कार्यों को शीघ्र पूरा करने की मांग उठाई। इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि क्षेत्र में कई सड़कें अधूरी पड़ी हैं, पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं और अनेक विकास कार्य बजट के अभाव में रुके हुए हैं। जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। गांधी ने कहा कि जब भी इन कार्यों के बारे में अधिकारियों से बात की जाती है तो उनका सीधा जवाब होता है कि इन कार्यों के लिए बजट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश सरकार के दावे केवल कागजों और भाषणों तक ही सीमित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने के लिए बार-बार झूठे दावे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को यह समझना चाहिए कि केवल पदों और अपने करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने से विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण व सुधार लंबे समय से लंबित है।

मौसम

हिमाचल में बर्फबारी से लौटी ठंड

अटल टनल के पास वाहन फंसे, 20 मार्च तक अलर्ट

एजेंसी (हि.स.)
शिमला

हिमाचल प्रदेश में मार्च के मध्य एक बार फिर ठंड लौट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। मौसम के इस बदले मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और राज्य का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जबकि यह सामान्य से करीब 0.6 डिग्री कम दर्ज किया गया है।

प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। सराहन में सबसे अधिक 29.5 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि सलूणी में 32 मिमी बारिश दर्ज हुई। इसके अलावा भावानगर में 29 मिमी, रामपुर में 28 मिमी, कटौला में 23.4 मिमी, भटियात में 23.1 मिमी, मनाली में 22 मिमी और भरमौर में 20.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। मंडी में 14.6 मिमी, बरठीं में 14.2 मिमी और शिमला में 12.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी का दौर आज भी जारी है। खदराला में 10.2 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि कल्पा में 6.4 सेंटीमीटर बर्फ गिरी। इसके अलावा गोंदला और जोत में करीब 3-3 सेंटीमीटर व कुकुमसेरी में 1.5 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी का यह दौर अभी जारी रह सकता है। कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र में सोमवार को भी मौसम खराब बना हुआ है। ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम खराब होने के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। हिल स्टेशनों शिमला और मनाली में ठंड बढ़ने के बाद लोगों ने एक बार फिर गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। बर्फबारी का असर यातायात पर भी पड़ा है।

कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी, फंसे वाहनों को निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया

श्रीनगर। कश्मीर के अधिकांश ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे कुछ हिस्सों में वाहनों की आवाजाही बाधित हुआ है। सिंथन टॉप पर भारी बर्फबारी के बाद कई वाहन फंस गए, जिसके बाद पुलिस और सेना ने फंसे हुए 214 पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए रविवार रात बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग, मध्य कश्मीर के बडगाम जिले के दूधपथरी और मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग के पर्यटक रिसॉर्ट्स में मध्यम बर्फबारी हुई। उन्होंने कहा कि दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में मुगल रोड पर पीर की गली, जोजिला अक्ष, उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा में गुरेज, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में साधना टॉप और दक्षिण कश्मीर में अनंतनाग को जम्मू क्षेत्र में किश्तवार से जोड़ने वाले सिंथन टॉप सहित ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। उन्होंने बताया कि साधना टॉप पर 12 इंच से अधिक ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि सिंथन टॉप पर लगभग छह इंच बर्फबारी हुई है। अधिकारियों ने कहा कि बर्फबारी के कारण घाटी में महत्वपूर्ण सड़क संपर्क बंद हो गए हैं, जिनमें गुरेज-बांदीपुरा रोड, सिंथन-किश्तवाड़ रोड और कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाली वैकल्पिक सड़क मुगल रोड शामिल है। उन्होंने कहा कि जोजिला दर्रे पर बर्फ जमा होने के कारण श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी निलंबित कर दी गई है। श्रीनगर समेत घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जो सोमवार सुबह तक रुक-रुक कर जारी रही। श्रीनगर शहर में पिछले 24 घंटों में 15.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। पहलगाम पर्यटन स्थल, जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए

हरियाणा विधानसभा में सदन सदस्यों ने दिवंगतों को दी श्रद्धांजलि

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ते हुए हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री हरविंद्र कल्याण की माता श्रीमती प्रेम कौर कल्याण के निधन तथा गुरुग्राम में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हुए हादसे में 7 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती प्रेम कौर कल्याण का 13 मार्च, 2026 को हुआ निधन अत्यंत दुःखद है।उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने की कामना की।

मुख्यमंत्री ने 9 मार्च को गुरुग्राम में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी के नीचे दबने से 7 लोगों की हुई दुःखद एवं असामयिक मृत्यु पर भी गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत पीड़ादायक घटना है और इस हादसे में दिवंगतों के परिवारों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं।इसके अलावा जींद जिले के सफीदों क्षेत्र में हुए हादसे में महिला श्रमिकों की मृत्यु पर भी गहरा दुःख व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस दुःख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉ कृष्ण लाल मिड्ढा ने भी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया।नेता प्रतिपक्ष श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पार्टी की ओर से दिवंगतों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके पश्चात सदन के सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

हरियाणा में अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण, सत्यापन की समय-सीमा बढ़ी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 तथा नियम, 2025 के तहत ६६६.शॄ४शीीस्त्र'ङ्क्टीीर.ॅ१८ल्लॅ.ङ्क५.ल्ल पोर्टल पर अनुबंध कर्मचारियों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय-सीमा एक माह के लिए बढ़ा दी है।मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में जारी पत्र के अनुसार, जिन अनुबंध कर्मचारियों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, वे 15 अप्रैल, 2026 तक पोर्टल पर पंजीकरण कर सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (डीडीओ) 25 अप्रैल, 2026 तक, कर्मचारियों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण को सत्यापित करेंगे और विभागीय सेवा रिकॉर्ड की जांच करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त विभाग द्वारा पात्र अनुबंध कर्मचारियों के लिए सुपरन्यूमेरेरी पद सृजित किए जाएंगे।यह प्रक्रिया 15 मई, 2026 तक पूरी की जाएगी।इसके बाद संबंधित विभागाध्यक्ष अंतिम स्वीकृति प्रदान करते हुए पात्र अनुबंध कर्मचारियों को 15 जून, 2026 तक सेवा सुरक्षा के लिए ऑफर लेटर जारी करेंगे।

पूर्व छात्र किसी भी विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी पूंजी: प्रो. सोमनाथ सचदेवा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय की असली पहचान उसके पूर्व छात्र होते हैं। पूर्व छात्र ही संस्थान की उपलब्धियों और परंपराओं को समाज तक पहुंचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जब पूर्व छात्र अपने विश्वविद्यालय से जुड़े रहते हैं तो इससे संस्थान की शैक्षणिक और सामाजिक प्रतिष्ठा और अधिक मजबूत होती है। उन्होंने यह विचार विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा 15 मार्च को डॉ. राधाकृष्णन सदन में आयोजित एलुमनी मीट 2026 के दौरान व्यक्त किए।

समारोह में विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रो. शशि आनंद, प्रो. नरेंद्र सिंह तथा वरिष्ठ प्रो. नीलम ढांडा विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में विभाग की स्थापना वर्ष 1971 से अब तक के विभिन्न बैचों के पूर्व छात्रों को आमंत्रित किया गया था। विभिन्न बैचों के पूर्व छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें विशेष रूप से 1988द1990 बैच के पूर्व छात्रों की सर्वाधिक उपस्थिति देखने को मिली। इसके साथ ही विभाग के व्यावसायिक पाठ्यक्रम एमआईबी, एमएमटी और एमएफसी के पूर्व छात्र भी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए।

कार्यक्रम की शुरूआत पूर्व छात्रों के पारंपरिक तिलक के साथ स्वागत से हुई। विभागाध्यक्ष प्रो. महावीर नरवाल ने सभी अतिथियों और पूर्व छात्रों का स्वागत करते हुए विभाग की उपलब्धियों और इतिहास पर प्रकाश डाला।इसके बाद दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विभाग की पुरानी यादों को संजोए एक विशेष वीडियो भी प्रदर्शित किया गया, जिसने उपस्थित पूर्व छात्रों को भावुक कर दिया।कई पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए विभाग से जुड़ी पुरानी यादों को सभी के साथ बांटा।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य और गायन की प्रस्तुतियों ने समारोह को और भी आकर्षक बना दिया। इसके अलावा ह्लचिट विद टास्कह्व नामक रोचक गतिविधि आयोजित की गई। एक विशेष गतिविधि के तहत पूर्व छात्रों ने अपने अंगूठे के निशान और हस्ताक्षर के साथ अपने बैच को स्मृति वृक्ष पर अंकित किया, जो इस मिलन समारोह की यादों का प्रतीक बना।

कार्यक्रम के अंत में पूर्व छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में प्रो. सुभाष चंद ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों, पूर्व छात्रों और आयोजकों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

स्वीडन प्रतिनिधिमंडल ने जानी आयुर्वेद उपचार पद्धति

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में स्वीडन के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, पंचकूला का दौरा किया और आयुर्वेद उपचार पद्धतियों को जाना। एनआईए में पहुंचने पर उप चिकित्सा अधीक्षक (डीएमएस) डॉ. गौरव गर्ग ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और उन्हें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों से अवगत कराया। वहीं, डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व ने प्रतिनिधिमंडल को संस्थान की कार्यप्रणाली और शैक्षणिक गतिविधियों बारे जानकारी दी। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद उपचार पद्धतियों की सराहना की। डॉ. गौरव गर्ग ने प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया गया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी के मार्गदर्शन में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जरिये रोगियों का उपचार किया जा रहा है। संस्थान की 12 ओपीडी में हर रोज 400 से 500 मरीज परामर्श और इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जिनका विशेषज्ञ चिकित्सकों के जरिये इलाज किया जाता है। मेडिकल ऑफिसर डॉ. शिन्षा ने प्रतिनिधिमंडल को संस्थान का दौरा कराया और उन्हें ओपीडी और आईपीडी के बारे में विस्तार से बताया। प्रतिनिधिमंडल ने ओपीडी और आईपीडी सेक्शन के साथ पंचकर्म, केंद्रीय लेबोरेट्री, फिजियोथैरेपी, फामेर्सी, पंजीकरण शाखा और आपरेशन थियेटर का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रही गबिजा गाडलियाउस्काइट और रीता जिलेनाइते ने पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की सराहना करते हुए कहा कि यूरोपीय देशों में आयुर्वेद उपचार की डिमांड बढ़ रही है और आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो रहा है।

नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता: प्रो. नीरा राघव

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा के मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेंटर (कुटिक) द्वारा स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग के द्वितीय चरण का मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवाचार आधारित स्टार्टअप्स का मूल्यांकन कर उन्हें वित्तीय सहयोग एवं विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करना है, ताकि युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की भावना को बढ़ावा मिल सके।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रसायन विभाग की प्रो. नीरा राघव ने कहा कि वर्तमान समय में नवाचार आधारित स्टार्टअप देश की आर्थिक प्रगति और आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में विकसित हो रहे नए विचारों को उचित मंच और संसाधन उपलब्ध कराए जाने से युवा उद्यमियों को अपने नवाचारों को सफल व्यवसाय में बदलने का अवसर मिलता है। स्टार्टअप्स के मूल्यांकन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति में डॉ. वर्षा सिंह, निदेशक, मेडजैक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड; तेजिंदर पाल सिंह जस्सल, निदेशक, पायलट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट लिमिटेड; तथा श्री विश्वेन्द्र सिंह मोर, वरिष्ठ प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शामिल रहे।

कार्यक्रम के दौरान तीन स्टार्टअप्स ने अपने नवाचार आधारित व्यावसायिक विचार प्रस्तुत किए। सुक्समा मेडजैक प्राइवेट लिमिटेड दवाओं की प्रभावी आपूर्ति के लिए माइक्रोनीडल पैच विकसित कर रहा है, जो दवा देने की अपेक्षाकृत कम दर्दनाक और प्रभावी तकनीक है।निवा हेल्थकेयर वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए एक समग्र हेल्थ मॉनिटरिंग समाधान तैयार कर रहा है, जिसके माध्यम से बुजुर्गों के विभिन्न स्वास्थ्य मानकों पर निरंतर निगरानी रखी जा सकेगी।वहीं चिकित्सम द्वारा एक स्मार्ट बैंड विकसित किया जा रहा है, जो शरीर के विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी कर स्वास्थ्य प्रबंधन में सहायक सिद्ध होगा। स्टार्टअप्स का मूल्यांकन उनके बिजनेस पिच, तकनीकी नवाचार, व्यवहारिकता तथा संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर किया गया।

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट (डॉ.) अजय जांगड़ा, समन्वयक, केयूटीआईसी ने बताया कि आगामी दिनों में कुल 14 स्टार्टअप्स का फंडिंग के लिए मूल्यांकन किया जाना प्रस्तावित है।उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहलें विश्वविद्यालय में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होंगी।कार्यक्रम के दौरान डॉ. प्रियंका जांगड़ा (निवा हेल्थकेयर की मेंटर), डॉ. भंवर सिंह, डॉ. हरदीप राय शर्मा तथा मनोज शर्मा भी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त-समाचार

कुवि में 30वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी आज

कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग द्वारा विभागीय कला दीर्घा में 30 वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी-2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 17 मार्च 2026 को प्रातः 10.30 बजे विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। विभागाध्यक्ष डॉ. गुरचरण सिंह ने बताया कि यह 30वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी विभाग की समग्र कला शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दशार्ती है। यह मंच युवा कलाकारों को अपनी सृजनात्मकता को अभिव्यक्त करने, अपनी कला दृष्टि को समाज के सामने रखने तथा अपने कौशल को निखारने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शनी नई सोच और रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगी। फाइन आर्ट्स विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर एवं संयोजक डॉ. मोनिका गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों और शोधार्थियों की 300 से अधिक उत्कृष्ट कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। प्रदर्शनी में पारंपरिक लोक कला से लेकर आधुनिक कला शैलियों जैसे एक्सप्रेशनिज्म और डिजिटल प्रिंटमेकिंग तक की झलक देखने को मिलेगी। प्रदर्शनी के आयोजन में डॉ. राकेश बानी, डॉ. सविप राज, अनिल, सोहन, विपिन कुमार और रवि कुमार सहित विद्यार्थियों व शोधार्थियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। सभी ने मिलकर कला दीर्घा को आकर्षक ढंग से सजाया है, जिससे प्रदर्शनी को एक जीवंत स्वरूप मिला है। इस प्रदर्शनी में ऑयल और ऐक्रिलिक पेंटिंग, चारकोल स्केच, वाटरकलर, धातु, पत्थर व लकड़ी की मूर्तियाँ, डिजिटल आर्ट, पोस्टर, विज्ञापन, वस्त्र कला तथा प्रायोगिक फोटोग्राफी सहित अनेक कलात्मक माध्यमों की कृतियाँ प्रदर्शित होंगी। यह वार्षिक कला प्रदर्शनी 20 मार्च 2026तक आम जनता के लिए खुली रहेगी, जिसमें कला प्रेमी, छात्र और शोधार्थी आकर विभिन्न कलाकृतियों का अवलोकन कर सकेंगे।

सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए किशोरियो का एचपीवी टीकाकरण करवाए

कुरुक्षेत्र। जिला सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह ने कहा कि जिले में 28 फरवरी 2026 से एचपीवी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 14 वर्ष से 15 वर्ष तक की किशोरियो को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिये एचपीवी वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है ताकि भविष्य में इस जानलेवा रोग होने की सम्भावना को समाप्त किया जा सके। जिला सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि एचपीची टीका पूरी तरह सुरक्षित है तथा सर्वाइकल कैंसर को मुख्य कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचाने में लगभग 90 प्रतिशत तक प्रभावी है। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन जिला नागरिक अस्पताल सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो में उपलब्ध है। अभी तक जिला में लगभग 100 किशोरियो का टीकाकरण किया गया है। इस अभियान में 14 वर्ष से 15 वर्ष के बीच की आयु की 7007 किशोरियों को यह टीका लगाया जाना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने समाज में फैली गलतफहमियों को दूर करते हुए स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म के दौरान भी यह टीका सुरक्षित रूप से लगाया जा सकता है। सिविल सर्जन ने बताया कि एचपीवी एक वायरल संक्रमण है जो कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षण के भी सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। भारत मे महिलाओं में होने वाले कैंसर के मामले में यह दूसरे नम्बर पर आता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैक्सीन अत्यंत प्रभारी है. इसलिए सभी अपनी 14 से 15 वर्ष की बेटियों के सुरक्षित स्वास्थ्य व अच्छे भविष्य के लिए एचपीवी टीकाकरण अवश्य करवायें।

एमडीयू ने बीबीए छठे सेमेस्टर (री-अपीयर) का परिणाम घोषित किया

चंडीगढ़। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (एमडीयू) रोहतक ने दिसंबर 2025 में आयोजित बीबीए, बीबीए (क्क), बीबीए (उअट) और बीबीए (इए) के छठे सेमेस्टर (री-अपीयर) की परीक्षाओं का परिणाम 16 मार्च 2026 को घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि विद्यार्थी अपना परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

35वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर प्रो. सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में हुई बैठक

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

- दीक्षांत समारोह में करीब 2800 विद्यार्थियों को डिग्रियां व 80 शोधार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आगामी 35वें दीक्षांत समारोह के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के डीन, अधिकारी तथा संबंधित शाखाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और समारोह से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह 4 अप्रैल, 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पीजी के करीब 1900, यूजी के 500 तथा आईआईएचएस के करीब 400 विद्यार्थियों सहित कुल 2800 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जबकि 80 शोधार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समारोह विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है, जिसमें विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए डिग्रियां और पदक प्रदान किए जाते हैं।इसलिए समारोह को गरिमामय और सुव्यवस्थित ढंग से आयोजित करना विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। कुलगुरु प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दीक्षांत समारोह से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि समारोह में आने वाले विशिष्ट अतिथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए उचित बैठने की व्यवस्था, स्वागत, सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। बैठक में समारोह के दौरान मंच व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति, डिग्रियों और मेडल वितरण की प्रक्रिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, आईटी सपोर्ट तथा मीडिया समन्वय सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों की जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता के साथ निभाएं और आपसी समन्वय बनाए रखें। बैठक में कुलसचिव प्रो. वीरेन्द्र पाल, डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रो. राकेश कुमार, डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. ब्रजेश साहनी, आईटी सेल हेड प्रो. प्रदीप मित्तल, प्रो. संजीव अग्रवाल, प्रो. प्रीति जैन, प्रो. नरेन्द्र सिंह, परीक्षा नियंत्रक डॉ. अंकेश्वर प्रकाश आदि मौजूद रहे।

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद के सानिध्य में नाथद्वारा में निकली ऐतिहासिक गीता सद्भावना यात्रा

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि राजस्थान के श्री तीर्थ राज नाथद्वारा की फिजा पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों से महक उठी।इस तीर्थ स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर गीता सद्भावना यात्रा को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का काम किया।इस यात्रा के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश हजारों लाखों लोगों तक पहुंचे है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद हरियाणा सरकार व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से नाथद्वारा राजस्थान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के गीता सद्भावना यात्रा में बोल रहे थे। इससे पहले गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज व विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने मंत्रोच्चारण और शंखनाद की ध्वनि के साथ गीता सद्भावना यात्रा का शुभारंभ किया। इस गीता सद्भावना यात्रा में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में हजारों लोगों ने भाग लिया और सांय कालीन आरती में भी लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया।

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने गीता के उपदेशों के माध्यम से जीवन में सकारात्मकता और सेवा भाव लाने पर प्रकाश डाला। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने महाराज जी को आश्वासन दिया कि मैं अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर प्रतिदिन गीता के पांच पृष्ठो का अध्ययन और मनन करूंगी। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंगल, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सीओ पंकज सेतिया, विकास बोर्ड सदस्य अल्केश मोदगिल एवं गीता जयंती महोत्सव अथॉरिटी से विजय नरूला, ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा के प्रधान महासचिव रामपाल शर्मा एवं गीता परिवार के देशभर से आये हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।

पिपली से कुरुक्षेत्र तक के तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए बोटिंग चलाने की योजना पर फोकस: धुमन सिंह

सिटी दर्पण संवाददाता
कुरुक्षेत्र

- चैत्र कृष्ण चौदस 18 मार्च को होगी अष्टकोशी यात्रा
- सुबह 5 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक पूरी की जाएगी यात्रा
- हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह ने किया कार्यक्रम स्थल का अवलोकन

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच ने कहा कि सरकार की तरफ से पिपली से कुरुक्षेत्र तक 6 किलोमीटर तक के सरस्वती नदी के तटों पर विकास कार्य चल रहा है और रिटेनिंग वॉल लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इतना ही नहीं सरकार की योजना है कि पिपली से कुरुक्षेत्र तक के तीर्थों का भ्रमण श्रद्धालुओं को बोटिंग के माध्यम से करवाने की योजना पर फोकस रख कर काम किया जा रहा है। सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुमन सिंह किरमच रविवार को अष्टकोशी यात्रा को लेकर कार्यक्रम स्थल का जायजा ले रहे थे।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र की प्राचीन और ऐतिहासिक परम्पराओं को जीवंत करने का प्रयास किया जा रहा है। इन प्रयासों में अष्टद्दोशी यात्रा भी शामिल है। यह अष्टकोशी यात्रा चैत्र कृष्ण चौदस 18 मार्च को सुबह 5 बजे शुरू होगी और सायं 6 बजे यात्रा का समापन होगा। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र की परिक्रमा वास्तव में सन्निहित सरोवर की परिक्रमा है इस तीर्थ का विस्तार चारों दिशाओं में दो दो कोस था तीर्थ के तट पर स्थापित मंदिरों में दान व स्नान की परम्परा सदियों से चली आ रही है कुरुक्षेत्र की अष्टकोशी परिक्रमा भी पितृ जनों की मुक्ति दिलाने वाली व अक्षय फल प्राप्त गामी होती है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र अष्टकोशी परिक्रमा हजारों साल पुरानी है सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों ने उपवास रख जन नियंता भगवान ने सृष्टि का निर्माण करने के लिए अष्टकोशी की परिक्रमा की और अपने-अपने देवत्व भार को ग्रहण कर सृष्टि संयोजन का कार्य प्रारंभ किया त्रिदेवों के पश्चात सैकड़ों सालों से सदैव प्रतिवर्ष देवता और धार्मिक पुरुषों ने अष्टकोशी भूमि की यात्रा अनवरत रूप से जारी रखी एक बार यात्रा करने पर मनुष्य की समस्त मनोकामना को पूरा करने वाली दो बार अष्टकोशी यात्रा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है तीन बार अष्टकोशी यात्रा करने पर अक्षय लोको की प्राप्ति होती है उन्होंने कहा कि आदिकाल से चली आ रही यह परिक्रमा साहसिक तीर्थ यात्रा है खेतों की छोटी-छोटी पगडंडी पर सरस्वती नदी के किनारे किनारे चलते हुए लगभग 24 किलोमीटर की यह यात्रा सूर्योदय से नाभि कमल मंदिर से चलकर नाभ कमल मंदिर में सूर्य अस्त तक पूर्ण होती है कुरुक्षेत्र मोक्षदायक धार्मिक प्रसिद्ध ऐतिहासिक तीर्थ है।यह केवल महाभारत युद्ध भूमि ही नहीं भगवान कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई गीता जन्मस्थली भी है राजा कुरु के अष्टांग योग यज्ञ,तप ,सत्य, क्षमा, दया, शौच ,दान ,ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण मोक्ष प्रदायक स्थान भी है।यह यात्रा नाभकमल तीर्थ से सरस्वती के किनारे ओजस तीर्थ और वहीं से सरस्वती के किनारे किनारे होते हुए स्थानेश्वर तीर्थ, कुबेर तीर्थ, बदर पाचन तीर्थ ,क्षीर सागर तीर्थ,पूर्व वाहिनी सरस्वती तीर्थ खेडी मारकंडा,दधीचि तीर्थ,वृद्ध कन्या तीर्थ ,रन्तुक यक्ष, पावन तीर्थ ,औघड़ तीर्थ ,बाणगंगा,उपगया तीर्थ, नरकातारी बाणगंगा से होते हुए नाभकमल पर समाप्त होती है।

सांसद कुमारी सैलजा ने लोकसभा में उठाया स्मार्ट सिटी परियोजना में अनियमितताओं का मुद्दा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

- करनाल में 356.87 करोड़ रुपये ऐसे कार्यों पर खर्च किए गए जो चिन्हित विकास क्षेत्र से बाहर थे
- अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच करवाई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए

सिरसा की सांसद, कांग्रेस की महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कुमारी सैलजा ने लोकसभा में स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में सामने आई गंभीर अनियमितताओं और अधूरी परियोजनाओं का मुद्दा उठाते हुए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के फरीदाबाद और करनाल सहित देश के कई शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का काम अपेक्षित गति से नहीं हुआ है और अनेक योजनाएं आज भी अधूरी पड़ी हैं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों शहरों में कुल 167 परियोजनाओं में से जून 2024 तक केवल 112 परियोजनाएं ही शुरू की जा सकीं, जबकि उनमें से भी 67 परियोजनाओं में तीन से चार वर्ष तक की देरी हुई है। नगर स्तरीय निगरानी समिति की 133 निर्धारित बैठकों के स्थान पर केवल 10 बैठकें आयोजित की गईं, जिससे परियोजनाओं की सही समीक्षा और निगरानी नहीं हो सकी।उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार 3896.82 करोड़ रुपये की प्रस्तावित वित्तीय व्यवस्था के मुकाबले केवल 1825.86 करोड़ रुपये (लगभग 46.86 प्रतिशत) ही जुटाए जा सके।

इसके अलावा करनाल में 356.87 करोड़ रुपये ऐसे कार्यों पर खर्च किए गए जो चिन्हित विकास क्षेत्र से बाहर थे। साथ ही परियोजनाओं की गुणवत्ता का स्वतंत्र मूल्यांकन भी नहीं कराया गया।

कुमारी सैलजा ने सरकार से मांग की कि इन अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच करवाई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए।

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग का कुमारी सैलजा ने समर्थन किया है।

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि मान्यवर कांशीराम जी का संघर्ष करोड़ों बहुजनों को अधिकार, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाने वाला रहा है।ऐसे महान समाज सुधारक को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाना देश की सामाजिक न्याय की भावना को और मजबूत करेगा।

संपादकीय

टैरिफ बदले बिना नहीं होगा डील: भारत-अमेरिका ट्रेड समझौते पर सरकार का रुख स्पष्ट

भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर एक महत्वपूर्ण संकेत सामने आया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर तब ही किए जाएंगे जब नई टैरिफ संरचना पूरी तरह लागू हो जाएगी। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब वैश्विक व्यापार व्यवस्था तेजी से बदल रही है और देश अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए नए रणनीतिक समझौते करने में जुटे हैं। भारत और अमेरिका लंबे समय से व्यापारिक सहयोग को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में शुल्क, बाजार पहुंच और नियमों से जुड़े मुद्दे अब भी समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर वार्ताएं जारी हैं। सरकार का कहना है कि नई टैरिफ नीति लागू होने के बाद ही इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि व्यापारिक संतुलन और राष्ट्रीय हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सके। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध पिछले एक दशक में काफी मजबूत हुए हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर से अधिक के स्तर तक पहुंच चुका है और आने वाले वर्षों में इसे 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए कई संवेदनशील मुद्दों पर सहमति बनाना जरूरी है, जिनमें आयात शुल्क, कृषि उत्पादों की पहुंच, डिजिटल व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे विषय शामिल हैं। सरकार के अनुसार नई टैरिफ संरचना का उद्देश्य व्यापारिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाना है। इसके माध्यम से ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जा रही है जहां भारतीय उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में शुल्क कम करके निर्यात और निवेश को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई जा रही है। यही कारण है कि भारत जल्दबाजी में किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बजाय एक संतुलित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता केवल द्विपक्षीय व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। वर्तमान समय में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े बदलाव हो रहे हैं। कई कंपनियां चीन पर निर्भरता कम करके वैकल्पिक बाजारों की तलाश कर रही हैं और भारत इस बदलाव का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका के साथ मजबूत व्यापारिक समझौता भारत के लिए निवेश, तकनीक और निर्यात के नए अवसर पैदा कर सकता है। हालांकि, व्यापार वार्ताओं में कई जटिल मुद्दे भी सामने आते हैं। अमेरिका लंबे समय से भारत से कृषि, डेयरी और चिकित्सा उपकरणों पर शुल्क कम करने की मांग करता रहा है। वहीं भारत अपने छोटे किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहता है। इसी प्रकार डेटा संरक्षण, ई-कॉमर्स नियम और डिजिटल कर जैसे मुद्दे भी दोनों देशों के बीच चर्चा का विषय रहे हैं। भारत के लिए यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए समझौते इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में अमेरिका के साथ संभावित समझौता भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। सरकार का कहना है कि नई टैरिफ संरचना लागू होने के बाद व्यापार वार्ताओं में अधिक स्पष्टता आएगी। इससे यह तय करने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में शुल्क कम किया जा सकता है और किन क्षेत्रों को सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समझौते से भारतीय उद्योग, कृषि और रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि भारत और अमेरिका के बीच संतुलित व्यापार समझौता होता है तो इससे दोनों देशों को व्यापक लाभ मिल सकता है। अमेरिका को भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जबकि भारत को उन्नत तकनीक, निवेश और निर्यात के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे विनिर्माण, आईटी सेवाओं, फार्मास्यूटिकल्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है। वहीं कुछ विशेषज्ञ यह भी चेतावनी देते हैं कि व्यापार समझौते में जल्दबाजी करना भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सरकार का यह रुख कि नई टैरिफ संरचना लागू होने के बाद ही समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इससे भारत को अपने आर्थिक हितों का बेहतर आकलन करने और मजबूत स्थिति में वार्ता करने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता केवल आर्थिक सहयोग का विषय नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। नई टैरिफ संरचना लागू होने के बाद यदि यह समझौता संतुलित और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ता है, तो यह वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की स्थिति को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

साझा चूल्हा: संकट से समाधान की राह

डॉ. प्रियंका सौरभ (हि.स)

रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर समय-समय पर देश में राजनीतिक बहस तेज हो जाती है। विपक्ष इसे आम आदमी पर बढ़ते आर्थिक बोझ के रूप में उठाता है, तो सत्ता पक्ष अंतरराष्ट्रीय बाजार और वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देता है। यह बहस लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, क्योंकि महंगाई और जीवनयापन की लागत सीधे जनता के जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन इस पूरे विमर्श में अक्सर एक महत्वपूर्ण पक्ष छूट जाता है–समाज की अपनी सामूहिक शक्ति और संकट के समय मिल-जुलकर समाधान खोजने की क्षमता।

भारतीय समाज की मूल संरचना ही सामूहिकता पर आधारित रही है। यहां परिवार केवल पति-पत्नी और बच्चों तक सीमित नहीं होता, बल्कि विस्तृत रिश्तों और समुदाय के साथ जुड़ा रहता है। गांवों में तो यह भावना और भी गहरी दिखाई देती है, जहां कठिन परिस्थितियों में पूरा समाज एक-दूसरे के साथ खड़ा होता है। इसी सामाजिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है -साझा चूल्हा। साझा चूल्हा केवल भोजन पकाने का साधन नहीं था, बल्कि वह सामूहिक जीवन की भावना का केंद्र था। सीमित संसाधनों के दौर में कई परिवार मिलकर एक ही चूल्हे पर भोजन बनाते थे। इससे ईंधन की बचत होती थी, श्रम का बंटवारा होता था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि समाज के लोगों के बीच संवाद और अपनापन बना रहता था। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं रहता था, बल्कि वह सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का अवसर बन जाता था।

समय के साथ जीवनशैली में बदलाव आया। तकनीकी विकास, शहरीकरण और आर्थिक प्रगति ने जीवन को सुविधाजनक तो बनाया, लेकिन सामूहिक परंपराओं को धीरे-धीरे कमजोर भी किया। आज लगभग हर घर में अलग रसोई और अलग चूल्हा है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन इसके साथ ही समाज में एक प्रकार की दूरी भी बढ़ी है। पड़ोस में रहने वाले लोग भी कई बार एक-दूसरे से अपरिचित रह जाते हैं। इसी संदर्भ में जब गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों की चर्चा होती है, तो हमें केवल राजनीतिक बहस तक सीमित रहने के बजाय सामाजिक दृष्टि से भी सोचने की आवश्यकता है। क्या हम अपनी परंपराओं से कोई ऐसी सीख ले सकते हैं जो आज की परिस्थितियों में भी उपयोगी हो ? साझा चूल्हा का विचार इसी दिशा में एक प्रेरक उदाहरण हो सकता है।

हमारे समाज में भंडारे और लंगर की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक आयोजनों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में हजारों लोग एक ही रसोई से भोजन प्राप्त करते हैं। वहां न जाति का भेद होता है, न आर्थिक स्थिति का। सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यह परंपरा केवल सेवा भावना ही नहीं, बल्कि सामाजिक समानता और एकता का भी प्रतीक है। यदि समाज ऐसे बड़े आयोजनों में सामूहिक रसोई को सहजता से स्वीकार कर सकता है, तो फिर रोजमर्रा के जीवन में इस विचार को अपनाने में संकोच क्यों ? यह आवश्यक नहीं कि हर जगह बड़े स्तर पर सामुदायिक रसोई स्थापित की जाए, लेकिन छोटे-छोटे स्तर पर भी सहयोग की भावना विकसित की जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी मोहल्ले या समुदाय के कुछ परिवार मिलकर सामूहिक रूप से भोजन बनाने की व्यवस्था कर सकते हैं, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब संसाधन सीमित हों या खर्च अधिक हो रहा हो।

यह विचार केवल आर्थिक बचत तक सीमित नहीं है। साझा चूल्हा समाज में सहयोग और संवाद की संस्कृति को भी मजबूत कर सकता है। जब लोग एक साथ बैठते हैं, काम करते हैं और भोजन साझा करते हैं, तो उनके बीच विश्वास और समझ बढ़ती है। सामाजिक तनाव कम होते हैं और समुदाय की एकजुटता मजबूत होती है। खेती-किसानी, पशुपालन या अन्य श्रमसाध्य कार्यों से जुड़े लोग इस भावना को अधिक अच्छी तरह समझते हैं। ग्रामीण जीवन में श्रम और संसाधनों का साझा उपयोग एक सामान्य बात है। खेतों में काम के दौरान कई परिवार मिलकर भोजन की व्यवस्था करते हैं। त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर भी सामूहिक भोजन की परंपरा देखने को मिलती है। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सरल और संतुलित बनाने का एक व्यावहारिक तरीका भी है।

इसके विपरीत, आधुनिक शहरी जीवन ने कई लोगों को सुविधाओं के बीच तो रखा है, लेकिन उन्हें सामाजिक ताने-बाने से कुछ हद तक दूर भी कर दिया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी जीवन की अवधारणा ने सामूहिकता की भावना को कमजोर किया है। लोग अपने घरों में सीमित हो गए हैं और पड़ोस या समुदाय के साथ उनका संपर्क कम होता जा रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि समाज में एक प्रकार का अकेलापन और अलगाव भी बढ़ रहा है।

ऐसे में साझा चूल्हा केवल आर्थिक या व्यावहारिक समाधान नहीं, बल्कि सामाजिक पुनर्संरचना का भी एक प्रतीक बन सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि समाज की असली ताकत केवल सरकारी नीतियों में नहीं, बल्कि लोगों के आपसी सहयोग और एकता में भी होती है। जब समाज संगठित होता है, तो वह कई समस्याओं का समाधान स्वयं खोज लेता है। बेशक, आज की परिस्थितियां पहले जैसी नहीं हैं। शहरों की जीवनशैली, काम के अलग-अलग समय और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के कारण हर जगह साझा चूल्हा लागू करना संभव नहीं हो सकता। लेकिन इस विचार का मूल संदेश–सहयोग और साझेदारी–आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। यदि समाज इस भावना को अपनाए, तो कई समस्याओं का प्रभाव स्वतः कम हो सकता है।

दरअसल, संकट के समय समाज की असली परीक्षा होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कठिन परिस्थितियां आईं, भारतीय समाज ने सामूहिकता और सहयोग के बल पर उनका सामना किया है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आर्थिक चुनौतियों तक, लोगों ने एक-दूसरे की मदद करके परिस्थितियों को संभाला है। यही हमारी सामाजिक संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत है। आज जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक और ऊर्जा संबंधी चुनौतियां सामने हैं, तब यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित न रहें, बल्कि सामाजिक समाधान की दिशा में भी सोचें। साझा चूल्हा इसी सोच का एक प्रतीक हो सकता है–एक ऐसा प्रतीक जो हमें बताता है कि संकट केवल समस्या नहीं, बल्कि अवसर भी हो सकता है।

यदि समाज में सहयोग और साझेदारी की भावना मजबूत हो, तो कई कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और समस्याओं का बोझ भी साझा हो जाता है। यही कारण है कि सामुदायिक जीवन की परंपराएँ सदियों तक हमारे समाज को स्थिर और मजबूत बनाए रखती रही हैं। अंततः यह समझना आवश्यक है कि साझा चूल्हा केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की एक संभावित दिशा भी हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता और परंपरा विरोधी नहीं हैं; बल्कि यदि दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए तो समाज और अधिक सशक्त बन सकता है।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी परंपराओं से मिलने वाले संदेश को समझें और उसे आधुनिक संदर्भों में लागू करने का प्रयास करें। यदि समाज सहयोग और साझेदारी की भावना को फिर से जीवित कर सके, तो केवल गैस सिलेंडर ही नहीं, बल्कि जीवन की कई अन्य चुनौतियां भी सहज रूप से हल हो सकती हैं। साझा चूल्हा अंततः एक विचार है–एक ऐसा विचार जो बताता है कि जब समाज एक साथ खड़ा होता है, तो संकट भी अवसर बन सकता है और कठिन समय भी एक प्रकार के उत्सव में बदल सकता है। यही भारतीय सामाजिक संस्कृति की असली पहचान और ताकत है।

(लेखिका, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

समान नागरिक संहिता पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के निहितार्थ

भारत एक बहुधर्मी, बहुसांस्कृतिक और विविधताओं से भरा राष्ट्र है। यहाँ विभिन्न धर्मों, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई कानून अलग-अलग रूप में लागू होते रहे हैं। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और परिवार से जुड़े अन्य मामलों में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी और अन्य समुदायों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ प्रचलित हैं। किंतु एक आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक राष्ट्र के रूप में यह प्रश्न लंबे समय से उठता रहा है कि क्या एक ही देश में नागरिकों के लिए अलग-अलग नागरिक कानून उचित हैं? इसी संदर्भ में समान नागरिक संहिता का विचार समय-समय पर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आता रहा है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय की एक टिप्पणी ने इस बहस को फिर से नई गति दे दी है। न्यायालय ने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है, हालांकि यह निर्णय न्यायपालिका का नहीं बल्कि संसद का विषय है। अदालत शरियत कानून 1937 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ कथित भेदभाव का प्रश्न उठाया गया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने संकेत दिया कि यदि इन प्रावधानों को हटाया जाता है तो कानून में एक प्रकार का खालीपन उत्पन्न हो सकता है और इसका स्थायी समाधान समान नागरिक संहिता के माध्यम से ही संभव है।

वस्तुतः समान नागरिक संहिता का प्रश्न एक कानूनी व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, यह संविधान में निहित समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए यह विषय केवल अदालतों या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, राजनीति और संवैधानिक आदर्शों के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौती भी है।

संविधान में निहित विचार

समान नागरिक संहिता का विचार भारतीय संविधान में प्रारंभ से ही मौजूद है। संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत रखा गया है, जिनका उद्देश्य सरकार को सामाजिक सुधार की दिशा में मार्गदर्शन देना है।

संविधान सभा में इस विषय पर व्यापक चर्चा हुई थी। संविधान निमार्ता भीमराव रामजी आंबेडकर का मानना था कि आधुनिक राष्ट्र में नागरिकों के अधिकार धर्म के आधार पर अलग-अलग नहीं होने चाहिए। हालांकि उस समय देश की सामाजिक परिस्थितियों और विभिन्न समुदायों की आशंकाओं को देखते हुए इसे तत्काल लागू करने के बजाय नीति निदेशक सिद्धांतों में रखा गया। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई थी कि समय के साथ सामाजिक सहमति बनने पर इसे लागू किया जा सके।

पर्सनल लॉ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत में अलग-अलग पर्सनल लॉ की व्यवस्था औपनिवेशिक काल की देन मानी जाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में अलग-अलग कानून लागू किए गए थे। स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था जारी रही, हालांकि

डॉ. मयंक चतुर्वेदी (हि.स)

समय-समय पर इसमें सुधार किए गए। आज भी हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और अन्य संबंधित कानून प्रभावी हैं, जबकि मुसलमानों के निजी मामलों में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट 1937 लागू होता है। इसी प्रकार ईसाई और पारसी समुदायों के लिए भी अलग-अलग कानून मौजूद हैं।

यह विविधता भारत की सामाजिक संरचना का हिस्सा अवश्य है, लेकिन कई बार यह व्यवस्था संविधान में प्रदत्त समानता और न्याय के सिद्धांतों से टकराती हुई भी दिखाई देती है। विशेषकर महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में यह प्रश्न अधिक गंभीर हो जाता है।

न्यायपालिका का दृष्टिकोण

भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर बल दिया है। कई महत्वपूर्ण मामलों में अदालतों ने यह टिप्पणी की है कि अलग-अलग पर्सनल लॉ के कारण नागरिकों के बीच असमानता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। न्यायालयों का यह भी मत रहा है कि जब व्यक्तिगत कानूनों के कारण महिलाओं के अधिकार प्रभावित होते हैं तो संविधान में निहित समानता के सिद्धांत को चुनौती मिलती है। हालिया सुनवाई में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यही संकेत दिया कि यदि पर्सनल लॉ के कुछ प्रावधानों को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर एक व्यापक और समान नागरिक कानून की आवश्यकता होगी।

महिला अधिकारों के संदर्भ में महत्व

समान नागरिक संहिता की चर्चा अक्सर महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में अधिक होती है। भारत में कई पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार पुरुषों की तुलना में सीमित रहे हैं। कुछ समुदायों में बहुविवाह की अनुमति, तलाक की असमान प्रक्रिया और विरासत में कम हिस्सा जैसे मुद्दे लंबे समय तक विवाद का कारण बने रहे हैं। इन परिस्थितियों में महिलाओं को न्याय पाने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन असमानताओं को समाप्त कर एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार करना है जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों और कानून धर्म के बजाय नागरिकता के आधार पर लागू हो।

राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्षता

भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। पंथनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखे। यदि नागरिक कानून धर्म के आधार पर अलग-अलग होंगे तो यह सिद्धांत व्यवहार में कमजोर पड़ सकता है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं को समाप्त करना नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों को धर्म से अलग करना है। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे विषय मूलतः नागरिक अधिकारों से जुड़े होते हैं, इसलिए इन पर समान कानून होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप माना जाता है।

उत्तराखंड में प्रारंभिक प्रयोग

भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उत्तराखंड में उठाया गया है। राज्य सरकार ने इसे लागू कर विवाह के अनिवार्य पंजीकरण, संपत्ति में बेटा-बेटी को समान अधिकार और विवाह व तलाक से जुड़े समान नियमों की व्यवस्था की है। इसे देश में एक प्रयोग के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह व्यवस्था सफल होती है तो भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण मॉडल बन सकती है।

राजनीतिक और सामाजिक विमर्श

समान नागरिक संहिता पर बहस नई नहीं है। संविधान सभा से लेकर आज तक यह विषय समय-समय पर चर्चा में आता रहा है। कई लोग इसे सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक कदम मानते हैं, जबकि कुछ समुदायों को आशंका है कि इससे उनकी धार्मिक परंपराओं पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए यह विषय केवल कानून बनाने का प्रश्न नहीं है, बल्कि व्यापक सामाजिक संवाद और विश्वास निर्माण की भी आवश्यकता है।

कुल मिलाकर कहना यही है कि सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करने का समय आ चुका है, किंतु अंतिम निर्णय संसद को ही करना होगा। यदि समान नागरिक संहिता को संविधान की भावना, सामाजिक सहमति और सभी समुदायों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाता है तो यह अधिक न्यायपूर्ण, आधुनिक और समावेशी भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

आज का राशिफल

मेष: आज आपका मन काफी शांत और संतुलित रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और सम्मान भी बढ़ सकता है। फिल्म या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। *(सिटी दर्पण)*

वृषभ: आज आपके जीवन में कोई अच्छी खबर आ सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में आपकी भूमिका और अधिकार बढ़ सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी और प्रदर्शन बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। *(सिटी दर्पण)*

मिथुन: आज दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान देने से बचें। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। महिला जातकों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मित्रों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण कुछ निराशा हो सकती है। *(सिटी दर्पण)*

कर्क: आज मानसिक शांति बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। आईटी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में नई रणनीति अपनाने का विचार कर सकते हैं। कमीशन या एजेंसी से जुड़े कामों में आर्थिक लाभ संभव है। *(सिटी दर्पण)*

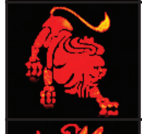

सिंह: राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कारोबार में आ रही बाधाओं को दूर करने में व्यस्त रह सकते हैं। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना है। बेरोजगार लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। *(सिटी दर्पण)*

कन्या: कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। लंबे समय से रुके कामों को पूरा करने का दबाव रहेगा। किसी रिश्तेदार से फोन पर बातचीत हो सकती है। जीवनसाथी के साथ अपने मन की बातें साझा करने से रिश्ते मजबूत होंगे। *(सिटी दर्पण)*

तुला: आज सहकर्मी आपसे अधिक उम्मीदें रख सकते हैं। बेवजह गुस्सा करने से बचें, वरना मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संपत्ति या जमीन से जुड़े निवेश में अच्छा अवसर मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

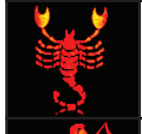

वृश्चिक: व्यापार में भाई-बहनों की मदद से काम आगे बढ़ सकता है। शेयर बाजार या निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। मार्केटिंग या सेल्स से जुड़े लोगों की आय में बढ़ोतरी हो सकती है। नई नौकरी शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। *(सिटी दर्पण)*

धनु: अधीनस्थ कर्मचारियों के सहयोग से आपके काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। दिन कुल मिलाकर शुभ संकेत दे रहा है। व्यापार में बड़ा निवेश करने का विचार बन सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। *(सिटी दर्पण)*

मकर: लंबे समय से रुके काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। अनुभवी और बुद्धिमान लोगों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। आपके विचारों को समाज और कार्यस्थल पर सम्मान मिलेगा। बैंकिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। *(सिटी दर्पण)*

कुंभ: आज जीवनसाथी का मूड थोड़ा खराब रह सकता है, इसलिए संयम बनाए रखें। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। परिवार में चल रहे विवादों से राहत मिल सकती है। तनाव से बचने के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी होगा। नए बदलावों को लेकर मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है। *(सिटी दर्पण)*

मीन: आज आपको अपनी क्षमता साबित करने का दबाव महसूस हो सकता है। प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। पुराने उधार या वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करना पड़ सकता है, जिससे कुछ योजनाएं रुक सकती हैं। *(सिटी दर्पण)*

फिर चली फूलों की बात, उत्तराखंड में खिला बुरांश

वसंत और फूल एक -दूसरे के पूरक हैं। जहां फूल हैं, वहां बारहों महीने वसंत है। वसंत है तो फूल हैं। फूल वसंत ऋतु के द्योतक हैं। वनों को प्रकृति का श्रृंगार कहा जाता है। फूल वनों का श्रृंगार हैं। वनों के श्रृंगार से आच्छादित प्रकृति वसंत ऋतु में रंग-बिरंगे फूलों के चित्ताकर्षक गहनों से सज-संवर जाती है। फूलों का यह गहना प्रकृति के सौंदर्य में चार-चांद लगा देता है। फूल को सौंदर्य, कमनीयता, प्रेम, अनुराग और मासूमियत का प्रतीक माना जाता है। फूल का रंग उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। प्रकृति के हरे परिवेश में सुर्ख लाल रंग के फूल खिल उठे हों तो यह दिलकश नजारा हर किसी का मन मोह लेता है।

उत्तराखंड के हरे-भरे जंगलों में चटक लाल रंग के बुरांश के फूलों का खिलना पहाड़ में वसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। वसंत के आते ही इन दिनों पहाड़ के जंगल बुरांश के सुर्ख लाल फूलों से मानो लद गए हैं। बुरांश ने धरती के गले को पुष्पाहार से सजा-सा दिया है। बुरांश के खिलने से प्रकृति का सौंदर्य निखर उठा है। बुरांश वसंत ऋतु में खिलने वाला फूल है। बुरांश जब खिलता है तो पहाड़ के जंगलों में बहार आ जाती है। घने जंगलों के बीच लाल बुरांश के फूलों के खिल उठने से जंगल के दहकने का भ्रम होता है। जब बुरांश के पेड़ लाल रंग के फूलों से ढक जाते हैं तो ऐसा आभास होता है कि मानो प्रकृति ने लाल चादर ओढ़ ली हो। इसीलिए बुरांश को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं।

उत्तराखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बुरांश की महत्ता एक पेड़ और फूल से कहीं बढ़कर है। बुरांश महज वसंत के आगमन का सूचक नहीं है, बल्कि सदियों से लोकगायकों, लेखकों, कवियों, घुमक्कड़ों और प्रकृति प्रेमियों की प्रेरणा का स्रोत भी रहा है। बुरांश उत्तराखंड के हरेक पहलू के समस्त रंगों को अपने में समेटे है। हिमालय के अनुपम सौंदर्य का वर्णन, प्रेयसी की उपमा, प्रेमाभिव्यक्ति, मिलन हो या विरह, बुरांश सभी प्रकार के लोकगीतों की भावाभिव्यक्ति का माध्यम है। उत्तराखंड के अनेक लोकगीत बुरांश के इर्द-गिर्द रचे गए हैं। विरह गीतों की मुख्य विषय-वस्तु बुरांश ही है। पहाड़ में बुरांश के खिलते ही कई भूले- बिसरे लोकगीत एकाएक स्वर पा जाते हैं।

बुरांश का खिलना प्रसन्नता का द्योतक है। बुरांश का फूल यौवन और आशावादिता का सूचक है। प्रेम और उल्लास की अभिव्यक्ति है। बुरांश का फूल मादकता जगाता है। बुरांश का गिरना विरह और नश्वरता का प्रतीक है। बुरांश रहित जंगल उदास और भावशून्य हो जाते हैं। इस पीड़ा को लोकगीतों के माध्यम से बखूबी महसूस किया जा सकता है।

प्रयाग पाण्डे (हि.स)

वसंत ऋतु में जंगल में बुरांश के फूलों को देखकर नव विवाहिताओं को अपने मायके और पति की याद सताने लगती है। रोजी-रोटी की तलाश में पहाड़ से पलायन करने को अभिशप्त अपने प्रियतम को याद कर वह कहती है - 'अब तो बुरांश भी खिल उठा है, पर तुम नहीं आए।' बुरांश के फूल में हिमालय की विराटता है। शिव जी की शोभा है। पार्वती जी की झिलमिल चादर है। शिव जी सहित सभी देवतागण बुरांश के फूलों से बने रंगों से होली खेलते हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध लोककवि चारु चन्द्र पाण्डे द्वारा लिखा गया बुरांश के फूल पर आधारित यह होली गीत लोकजीवन में बुरांश की गहरी पैठ को उजागर करता है:

'बुरुंशी का फूलों को कुमकुम मारो,
डाना -काना छाजि गै बसंती नारंगी।
पारवती ज्यूकि झिलमिल चादर,
ह्यूं की परिन लै रंगै सतरंगी।
लाल भई छहिमांचल रेखा,
शिव जी की शोभा पिङलि दनिकारी।
सूरिजा की बेटियों लै सरग बै रंग घोलि,
सारी ही गागरि ख़्वारिन खिति डारी।......

बुरांश ने लोक रचनाकारों को कलात्मक उन्मुक्तता, प्रयोगशीलता और सौंदर्यबोध दिया। पहाड़ के लोकगीतों में सबसे ज्यादा जगह बुरांश को ही मिली। होली से लेकर प्रेम, सौंदर्य और विरह सभी प्रकार के लोकगीतों के भावों को व्यक्त करने का माध्यम बुरांश बना। एक पुराने लोकगीत में जंगल में झक खिले बुरांश को देख मां को ससुराल से अपनी बिटिया के आने का भ्रम होता है। वह कहती है -'वहां उधर पहाड़ के शिखर पर बुरुंश का फूल खिल गया है। मैं समझी मेरी प्यारी बिटिया हीरू आ रही है। अरे ! फूलों से झक -झक लदे बुरुंश के पेड़ को मैंने अपनी बिटिया हीरू का रंगीन पिछौड़ा समझ लिया।' गढ़वाल के प्रसिद्ध कवि चंद्र मोहन रतूड़ी ने नायिका के होठों की लालिमा का जिक्र कुछ यूं किया है -'चोरिया कना ए बुरासन ओंठ तेरा नाराणा।' यानी

'बुरांश के फूलों ने हाय ! राम तेरे होठ कैसे चुरा लिए।'

संस्कृत के अनेक कवियों ने बुरांश की महिमा को लेकर श्लोकों की रचना की है। प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत भी बुरांश के अदभुत सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने बुरांश पर कुमाउंनी भाषा में कविता लिखी थी:-

'सार जंगल में त्वीं जस क्वे न्हां रे क्वे न्हां,
फुलन छै के बुरूंश जंगल जस जलि जां,
सल्ल छ, दयार छ, पई छ, अंयार छ।
सबनाक फागन में पुड़नक भार छ,
पै त्वी में दिलैकि आग त्वी में ज्वानिक फाग छ,
रगन त्यार ल्वे छ,
प्यारक खुमार छ.....। 'भावार्थ यह है -'सारे जंगल में तेरे जैसा कोई नहीं रे, कोई नहीं।जब तू खिलता है, जंगल के जलने का भ्रम होता है। जंगल में साल है, देवदार है, पईया है और अयार सहित विभिन्न प्रजातियों के पेड़ हैं। सबकी शाखाओं में कलियों का भार है। लेकिन तुझमें जवानी का फाग है। तेरे रगों में लौ है, प्यार का खुमार है।' पहाड़ के रोजमर्रा के जीवन में बुरांश किसी वरदान से कम नहीं है। बुरांश के फूल बहुउपयोगी हैं। बुरांश के फूलों से जूस और शरबत बनता है। इसके फूल से प्राप्त शहद का दवा के रूप में उपयोग होता है। बुरांश के फूल के शहद को बेहद स्वास्थवर्धक माना जाता है। बुरांश के फूलों के रस को सीधे चूसकर भी खाया जा सकता है। इसके फूलों का अचार भी बनाया जा सकता है। बुरांश के फूलों के जूस को हृदयरोग और महिलाओं को होने वाले सफेद प्रदर रोग के लिए रामबाण दवा माना जाता है। बुरांश की पत्तियों का आयुर्वेदिक दवाओं में उपयोग किया जाता है। बुरांश की लकड़ी स्थानीय कृषि उपकरणों से लेकर जलावन तक सभी काम आती है। चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष होने के चलते बुरांश का वृक्ष जल संग्रहण में मददगार है। पहाड़ी इलाकों में जल स्रोतों को जिंदा रखने में बुरांश के पेड़ों का बड़ा योगदान है। इनके पेड़ों की जड़ें भू-क्षरण रोकने में भी असरदार मानी जाती हैं। बुरांश का खिला हुआ फूल करीब एक पखवाड़े तक अपनी चमक बिखेरता है। बाद में एक-एक कर इसकी पंखुड़ियां जमीन में गिरने लगती हैं। पलायन के कारण वीरान होती चली जा रही पहाड़ के गांवों की बाखलियों की तरह।

बुरांश सदाबहार वृक्ष है। भारत में बुरांश के वृक्ष उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में करीब तेरह सौ से छत्तीस सौ मीटर की मध्यम ऊंचाई वाले मध्य हिमालयी क्षेत्र में होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बुरांश को राज्य वृक्ष घोषित किया है। नेपाल में बुरांश के फूल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया है। बुरांश के पेड़ भारत के अलावा नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत, चीन और जापान आदि देशों में पाए जाते हैं। अंग्रेज इसे रोहडोडेंड्रॉन कहते हैं। विश्व में बुरांश की छह सौ से अधिक प्रजातियों का पता चल चुका है। प्रजाति, ऊंचाई और स्थानिक जलवायुगत विशेषताओं के चलते बुरांश के फूलों का रंग भी अलग-अलग होता है। सूर्ख लाल, गुलाबी, पीला और सफेद। ऊंचाई बढ़ने के साथ बुरांश के फूलों का रंग भी बदल जाता है। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बुरांश के फूल का रंग लाल होता है। जबकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका रंग सफेद होता है।

उत्तराखंड के जंगलों में वनावरण क्रमशः कम होता जा रहा है। इसी अनुपात में बुरांश के पेड़ भी कम हो रहे हैं। अवैध कटान और वनाग्नि के कारण पहाड़ के कई इलाकों में बुरांश लुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। जंगलों में बुरांश की नई पौध कम नजर आ रही हैं। जानकारों की राय में पर्यावरण संरक्षण के लिए बुरांश का संरक्षण भी जरूरी है। अगर बुरांश के जंगल के कम होने की मौजूदा रफ्तार जारी रही तो आने वाले कुछ सालों में बुरांश खिलने से इनकार कर देगा। परिणामस्वरूप आत्मीयता के प्रतीक बुरांश के फूलों के साथ पहाड़ के जंगलों की रौनक भी खत्म हो जाएगी। बुरांश सिर्फ पुराने लोकगीतों में ही सिमट कर रह जाएगा। वसंत ऋतु फिर आएगी। लेकिन बुरांश विहीन पहाड़ में वंसत के क्या मायने रह जाएंगे। नीरस और फीका वंसत?

(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

खेलों के बुनियादी ढांचे और युवाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक प्रयास: भगवंत मान

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सरकार ने चार साल पूरे होने पर खेलों की उपलब्धियों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब गांवों के खेल मैदानों में ऐतिहासिक निवेश कर रहा है और 1,100 करोड़ रुपए के निवेश से 3,000 आधुनिक खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, 6,000 और खेल मैदानों पर काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और सभी गांवों के खेल मैदानों में क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के मैदानों सहित मुफ्त खेल किट प्रदान की जाएंगी, ताकि हर युवा को खेलने का मौका मिल सके।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, युवाओं में स्वास्थ्य और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए गांवों में 6,000 इंडोर जिम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, ओलंपिक पदक विजेता पंजाबी हॉकी खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरियां मिली हैं, जबकि महिला क्रिकेट विश्व कप-2025 की विजेताओं को 4.91 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया है।

ग्रामीण विकास की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पिछले चार सालों में 76,000 परिवारों को अपने घर बनाने के लिए सहायता मिली है, जिसमें बाढ़ प्रभावित 30,000 परिवार भी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा, पिछली सरकार ने पांच सालों में 39,000 घर बनाए, जबकि वर्तमान सरकार ने सिर्फ चार सालों में 76,000 परिवारों को सहायता दी है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, 40,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण लिंक सड़कों का नवीनीकरण किया जा रहा है और यह पंजाब के इतिहास में एक साल में अब तक की सबसे बड़ी सड़क नवीनीकरण योजना है। उन्होंने आगे कहा, ये सड़कें पांच साल की रखरखाव गारंटी के साथ बनाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, पूरे पंजाब में कुल 13,414 गांवों के तालाबों की सफाई की गई है, जबकि राज्य की 36 मंडियों में सोलर पैनल लगाए गए हैं और 664 को शेड से ढककर पूरे राज्य की मंडियों को अपग्रेड किया गया है। उन्होंने आगे कहा, मनरेगा के तहत लगभग 9 लाख मजदूरों को रोजगार मिला है, जिससे 1,100 करोड़ रुपए मजदूरी पर खर्च हुए हैं और 2.3 करोड़ कार्य दिवस पैदा हुए हैं।

कृषि सुधारों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब के इतिहास में पहली बार किसानों को सिंचाई के लिए दिन में आठ घंटे निर्बाध बिजली मिल रही है। उन्होंने आगे कहा, लंबे समय से बंद पड़े कुल 18,349 नहरों को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे अब किसानों के खेतों में नहरी पानी पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, पंजाब के किसानों को गन्ने के लिए प्रति क्विंटल 416 रुपये मिल रहे हैं, जो देश में सबसे अधिक कीमत है। उन्होंने आगे कहा, किसानों को फसलों के नुकसान के लिए 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिला है, जो भारत में सबसे अधिक है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किसानों को सब्सिडी पर कुल 1.58 लाख फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें प्रदान की गई हैं। उन्होंने आगे कहा, फसलों की तुरंत खरीद की जा रही है और किसानों को समय पर भुगतान किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए और अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं को 1,500 रुपए उनके बैंक खातों में मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा, पंजाब की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना भी शुरू की गई है और हर साल 14.5 करोड़ से अधिक मुफ्त बस यात्राओं का लाभ उठाया जा रहा है।

उन्होंने आगे कहा, पिछले चार सालों में पेंशन योजनाओं में कुल 5.2 लाख नए लाभार्थी शामिल किए गए हैं और 35.7 लाख लोगों को 23,102 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, 4,400 वर्करों की भर्ती और 6,100 और भर्तियों के जारी होने से आंगनवाड़ी सेवाओं को मजबूत किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा, 27,314 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हर महीने मुफ्त सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं और अब तक 13.7 लाख महिलाओं को 7.4 करोड़ सैनिटरी पैड वितरित किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब के 90 प्रतिशत घरों को अब जीरो बिजली बिल आता है, जिससे परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा, पंजाब के इतिहास में पहली बार बिजली की दरें घटाई गई हैं, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट 1.5 रुपए, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 79 पैसे और उद्योगों के लिए 74 पैसे की कटौती की गई है।

उन्होंने आगे कहा, पंजाब सरकार ने 540 मेगावाट क्षमता वाला जी.वी.के. प्राइवेट पावर प्लांट खरीदा है, जिससे बिजली उत्पादन की लागत कम करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पी.एस.पी.सी.एल., जो पहले घाटे में चल रहा था, अब लगातार तीन साल से मुनाफे में है और भारत सरकार से सबसे ऊंचा ए+ रेटिंग प्राप्त किया है।

उन्होंने यह भी कहा, पछवाड़ा कोयला खदान से सस्ता कोयला खरीदकर सरकारी खजाने में 1,000 करोड़ रुपए की बचत की गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, रोशन पंजाब पहल के तहत बिजली ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को मजबूत करने तथा 247 बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है।

रोजगार सृजन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार ने राज्य में रोजगार क्रांति शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, पिछले चार सालों में युवाओं को सिफारिश या रिश्वत के बिना सिर्फ योग्यता के आधार पर 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, पिछले चार सालों के दौरान पंजाब में रिकॉर्ड औद्योगिक निवेश से लगभग 5.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

नशे के खिलाफ अभियान पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 'युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ निर्णायक और सख्त कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा, कुल 68,389 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 92,264 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, 5,480 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई है, जो देश भर में जब्त की गई सबसे बड़ी खेप है। उन्होंने कहा, नशा तस्करों से संबंधित 760 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है, जबकि 64 हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, राज्य भर में 1.5 लाख से अधिक सदस्यों वाली विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई गई हैं, जो नशे के खिलाफ सरकार की आँखें और कान के रूप में काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, इन कमेटियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर 600 से अधिक नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, पिंड दे पहरेदार गांवों और वार्डों में तैनात किए गए हैं ताकि समुदायों को नशे के खिलाफ जागरूक रखा जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, चार सालों में नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में बेडों की संख्या 1,455 से बढ़ाकर 5,255 कर दी गई है, जो 360 प्रतिशत की वृद्धि दशार्ती है, और सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए विशेष नशा विरोधी पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

कानून व्यवस्था पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब सरकार द्वारा गैंगस्टरों पर वार और ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि संगठित गिरोह पंजाब में पैर न पसार सकें। उन्होंने आगे कहा, अब तक 12,000 पुलिस कर्मियों वाली टीमों द्वारा 44,424 स्थानों पर छापेमारी की गई है, जिससे 14,722 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 711 फरार अपराधी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, इस कार्रवाई के तहत 76 आतंकवादी मॉड्यूल का पदार्फाश किया गया और 486 आतंकवादियों तथा कट्टरपंथियों को बड़ी मात्रा में हथियारों, विस्फोटकों और ग्रेनेडों सहित पकड़ा गया है, जिससे आतंकवादी नेटवर्क की रीढ़ तोड़ दी गई है। उन्होंने आगे कहा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार पंजाब की अपराध दर घटकर प्रति लाख व्यक्ति पर 227 अपराध हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत 448 का लगभग आधा है और हरियाणा की 740 की अपराध दर से तीन गुना कम है।

1962, 1965 और 1971 की जंगों में शहीद सैनिकों के परिवारों को मुआवजा देने संबंधी मोहिंदर भगत ने अधिकारियों के साथ बैठक की

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण, स्वतंत्रता सेनानी और बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज 1962, 1965 और 1971 की जंगों में शहीद हुए सैनिकों के उन परिवारों को मुआवजा राशि जारी करने संबंधी, जो अभी तक इससे वंचित रह गए हैं, संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि इन जंगों में शहीद हुए अधिकांश सैनिकों के परिवारों को पंजाब सरकार की ओर से पहले ही मुआवजा जमीन और नकद राशि के रूप में दिया जा चुका है। इसके अलावा शेष बचे मामलों और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर मंत्री मोहिंदर भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों से संबंधित सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा राशि मिल सके।

उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते हुए अपनी जान न्योछावर करने वाले बहादुर सैनिकों के प्रति पंजाब सरकार पूर्ण सम्मान और श्रद्धा रखती है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी हर संभव सहायता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बैठक में रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव अमरिंदर सिंह टिवाणा, निदेशक रक्षा सेवाएं कल्याण भूपिंदर सिंह ढिल्लों (सेवानिवृत्त), कमांडर बलजिंदर विर्क (सेवानिवृत्त), राजस्व विभाग से अधीन सचिव परविंदर कौर पाल तथा लीगल रिमेम्ब्रेंसर विभाग से संयुक्त एल.आर. उदयपाल सिंह हुंदल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

स्पीकर द्वारा पंजाब विधानसभा हॉल में मौजूदा विधायकों की लगाई गई तस्वीरों का उद्घाटन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

पंजाब विधानसभा में पंजाब विधानसभा के 117 सदस्यों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिनमें पंजाब विधानसभा के स्पीकर, पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और विपक्ष के नेता शामिल हैं। इनका उद्घाटन आज पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने किया। उद्घाटन के दौरान कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा , कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद थे।

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज अपने चैंबर में इस वर्ष सिविल सेवाएं परीक्षा पास करने वाले पंजाब के विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने पंजाब विधानसभा की कार्यवाही भी देखी। स्पीकर ने सिविल सेवाएं परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच सही अंतर के बारे में भी बताया।

स्पीकर संधवां ने विद्यार्थियों को लोई और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां, हरदीप सिंह मुंडियां और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी इन विद्यार्थियों को बधाई दी।

संक्षिप्त-समाचार

हैदराबाद में गुरुद्वारा साहिब की जगह पर जबरदस्ती कब्जा करने का शिरोमणि कमेटी ने नोटिस लिया

जैतो। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने हैदराबाद में गुरुद्वारा साहिब बरमबाला की जगह पर जबरदस्ती कब्जा करने के लिए लोकल प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब की जगह पर इस तरह जबरदस्ती कब्जा करना न सिर्फ. दर्दनाक है, बल्कि इससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रही है। एडवोकेट धामी ने कहा कि गुरुद्वारा साहिब बरमबाला को जो जगह पुराने जमाने से मिली हुई है, उस पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करना कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। गुरुद्वारा साहिब के साथ इस तरह की जबरदस्ती किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सिख धर्म में गुरुद्वारे संगत की आस्था और विश्वास का सैंटर हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई के नाम पर गुरुद्वारा साहिब की जगह पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं पर हमला है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दमनकारी कार्रवाई से तुरंत पीछे हटना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील की कि वह इस मामले में तुरंत दखल दे और सिख समुदाय की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्थानीय राज्य सरकार को गुरुद्वारा साहिब बरमबाला से जुड़ी जगह पर कब्जे के इरादे से की जा रही कार्रवाई को पूरी तरह रोकने का आदेश दे। उन्होंने इस मामले में स्थानीय संगत के प्रति शिरोमणि कमेटी की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि सिख संगठन किसी भी दमन के खिलाफ पूरी दुनिया की संगतों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।

पंजाब विधानसभा द्वारा दो अहम बिल पारित

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा ने आज दो महत्वपूर्ण बिल पारित किए। इनमें पहला बिल पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एंड स्टॉकिस्ट एंड रिटेलर्स (संशोधन) बिल, 2026 है, जिसे पंजाब के जल संसाधन एवं खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल द्वारा पेश किया गया और सदन ने इसे बहुमत से पारित कर दिया। दूसरा बिल श्री गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, पंजाब बिल, 2026 है, जिसे पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया था। इस बिल को सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। सदन ने सर्वसम्मति से एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार से प्रमुख दलित नेता और समाज सुधारक कांशी राम को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की सिफारिश की गई। सदन ने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के विरुद्ध की गई अपमानजनक और जातिवादी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। यह प्रस्ताव विधायक मनजीत सिंह बिलासपुर द्वारा पेश किया गया था। इससे पहले सदन में 11 रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गईं, जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के वित्त से संबंधित रिपोर्ट, मार्च 2023 तक के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर रिपोर्ट, मार्च 2023 तक के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के राजस्व से संबंधित रिपोर्ट और इसी अवधि के लिए कैग की एक अन्य रिपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के परफॉर्मेंस ऑडिट तथा पंजाब में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन पर कैग की रिपोर्ट, मार्च 2024 तक के वित्तीय वर्ष के लिए राज्य के राजस्व संबंधी रिपोर्ट, मार्च 2024 तक के वित्तीय वर्ष के लिए एक अन्य रिपोर्ट और मार्च 2023 तक के वित्तीय वर्ष के लिए स्थानीय निकायों से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2024-25 के लिए पंजाब सरकार के वित्त खाते (भाग-1), वित्त खाते (भाग-2) और विनियोजन खाते भी सदन के समक्ष रखे गए। इसके साथ ही बुड्ढा दरिया और घग्गर दरिया के संबंध में चेयरमैन समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। इसके अलावा वर्ष 2026-27 के लिए चयनित समितियों के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव भी सदन में प्रस्तुत किया गया।

खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने विपक्ष नेता को कड़े हाथों लिया

चंडीगढ़। पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज राज्य की खनन आय को 20,000 करोड़ रुपये तक ले जाने संबंधी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को कड़े हाथों लिया। खनन गतिविधियों से लगभग 20,000 करोड़ रुपये की आय संभव होने संबंधी पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कैबिनेट मंत्री ने तथ्यों सहित जवाब दिया और साथ ही बाजवा से पूछा कि पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान खनन राजस्व कभी 120 करोड़ रुपये से ऊपर क्यों नहीं गया? उन्होंने कहा कि चल रहे खनन सुधारों और नीतिगत पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र से राज्य की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार द्वारा पोटाश की खोज और प्रगतिशील खनन सुधारों के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। माइनिंग से अनुमानित राजस्व संबंधी अपने पहले दिए गए बयान को स्पष्ट करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पंजाब विधानसभा में कहा कि यह अनुमान राजस्थान से सटे पंजाब के कुछ क्षेत्रों, विशेष रूप से फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जैसे जिलों में पहचाने गए पोटाश खनिज भंडारों की विशाल संभावनाओं पर आधारित है। उन्होंने बताया कि पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज है, जिसका लगभग 96 प्रतिशत देश द्वारा आयात किया जाता है और पंजाब में इसकी मौजूदगी की संभावनाओं के बारे में पिछली सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से कोई गंभीर पड़ताल नहीं की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के समक्ष लगातार उठाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मंचों पर खनन मंत्रियों की बैठकों के दौरान तथा पंजाब में खोज कार्यों में तेजी लाने की अनुमति देने के लिए आधिकारिक संवाद माध्यमों से इस मुद्दे को बार-बार मजबूती से उठाया गया।

गैंगस्टरां ते वार का 55वां दिन: पंजाब पुलिस ने 363 स्थानों पर की छापेमारी; 172 गिरफ्तार

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निदेर्शों पर शुरू की गई निर्णायक गैंगस्टरां ते वार मुहिम के 55वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के चिन्हित और मैप किए गए 363 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरां ते वार पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए एक निर्णायक अभियान है, जिसकी शुरूआत 20 जनवरी 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने की थी। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पंजाब (एजीटीएफ) के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें पूरे राज्य में विशेष अभियान चला रही हैं।

अभियान के 55वें दिन पुलिस टीमों ने 172 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 3 हथियार बरामद किए। इसके साथ ही इस मुहिम की शुरूआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 14,894 हो गई है। इसके अलावा 77 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है, जबकि 72 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 3 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 के माध्यम से गुप्त रूप से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना साझा कर सकते हैं।

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम युद्ध नशों विरुद्ध को 380वें दिन भी जारी रखते हुए आज 91 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 706 ग्राम हेरोइन, 364 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 1.37 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 380 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की कुल संख्या 53,853 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 21 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार करवाने के लिए भी प्रेरित किया।

मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के लिए पंजाब बजट 2026-27 में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान इसे और मजबूत करेगा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

भगवंत मान सरकार ने पंजाब बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री सेहत योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित कर-के सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। यह आवंटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा पहल को और सुदृढ़ करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वर्ग से संबंधित परिवार आर्थिक तंगी के कारण गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित न रहे। चिकित्सीय आपात स्थिति के समय अधिकांश परिवारों के सामने अक्सर दो बड़े प्रश्न होते हैं–इलाज कितनी जल्दी शुरू हो सकेगा और खर्च का प्रबंध कैसे होगा। पिछले कुछ महीनों में पंजाब भर के परिवारों को मुख्यमंत्री सेहत योजना, जो कि एक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है और जिसकी पहुंच पूरे राज्य में लगातार बढ़ाई जा रही है, के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं। इस योजना के लिए पंजाब सरकार ने 2026-27 के बजट में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, ताकि इसका और विस्तार किया जा सके और पंजाब के परिवारों को सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा सके। यह कार्यक्रम अब पंजाब भर में लगभग 65 लाख परिवारों को कवर कर रहा है, जिससे लगभग 3 करोड़ निवासियों को लाभ मिल रहा है और गंभीर बीमारी के कारण आने वाले आर्थिक बोझ से सुरक्षा मिल रही है। इस कार्यक्रम की बढ़ती पहुंच राज्य में नामांकन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी साझेदारियों के तेज विस्तार से स्पष्ट दिखाई देती है। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे लाभार्थियों को 820 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल रही है। वर्तमान में यह योजना 2,300 से अधिक उपचार पैकेज प्रदान करती है, जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। इस योजना के लिए बजट में बढ़ाए गए प्रावधान के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बीमारी के कठिन समय में परिवारों को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है–जरूरत पड़ने पर पंजाब के हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से चिकित्सा खर्चों के आर्थिक बोझ से जूझ रहे राज्य के हजारों परिवार अब इलाज तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारियां, ऑर्थोपेडिक प्रक्रियाएं और दुर्घटना में लगी चोटों सहित कई गंभीर चिकित्सीय स्थितियों का इलाज बिना किसी खर्च के करवा सकते हैं। यह कवरेज सुनिश्चित करती है कि इलाज का निर्णय परिवार की आर्थिक क्षमता के बजाय चिकित्सीय आवश्यकता के आधार पर हो। हाल के वर्षों में 1500 से अधिक डॉक्टरों की नियुक्ति के माध्यम से पंजाब भर में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया गया है। इनमें 600 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टर और 900 से अधिक सामान्य चिकित्सक शामिल हैं, जो वर्तमान में पंजाब में कार्यरत डॉक्टरों का लगभग 35 प्रतिशत हैं। पंजाब सरकार पात्र निवासियों को मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत कैशलेस इलाज का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी सेवा केंद्रों और कॉमन सर्विस सेंटरों में स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2016 में ही बाबू कांशी राम जी के लिए भारत रत्न की मांग की थी: हरपाल सिंह चीमा

बाबू कांशी राम जी के लिए भारत रत्न की मांग वाला वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश प्रस्ताव विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

देश द्वारा उनकी 92वीं जयंती मनाए जाने के ठीक एक दिन बाद, प्रख्यात समाज सुधारक और राजनीतिक नेता बाबू कांशी राम जी को भारत रत्न देने की मांग करता एक ऐतिहासिक प्रस्ताव आज पंजाब विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से अपील की गई है कि वह बाबू कांशी राम जी को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान करे। इस प्रस्ताव को पूरे सदन में सर्वसम्मति से समर्थन मिला और पंजाब सरकार इस मजबूत सिफारिश को केंद्र सरकार को भेजेगी।

प्रस्ताव पेश करते हुए महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, बाबू कांशी राम जी ने बाबा साहेब डॉ. बी.आर. आंबेडकर की विचारधारा के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामाजिक-आर्थिक समानता का संदेश हर घर तक पहुंचाया। बाबू कांशीराम जी असाधारण ईमानदारी के प्रतीक थे। उन्होंने अपने नाम पर किसी भी प्रकार की संपत्ति, जमीन या बैंक खाता नहीं रखा और इसी तरह इस दुनिया को अलविदा कहा।

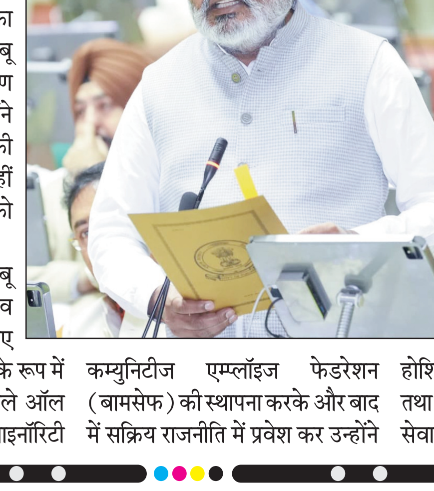

उन्होंने आगे कहा, बाबू कांशी राम जी ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पुणे में एक गजेटेड अधिकारी के रूप में अपना करियर छोड़ दिया। पहले ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन (बामसेफ) की स्थापना करके और बाद में सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर उन्होंने गरीब और मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले हजारों युवाओं को राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में उतरने के लिए सशक्त किया।

नेता के जीवन और राजनीतिक सफर पर प्रकाश डालते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, बाबू कांशी राम जी का जन्म 15 मार्च 1934 को रोपड़ के ख्वासपुरा गांव में हुआ था और उन्होंने सरकारी कॉलेज रोपड़ से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बाद में उन्होंने 1991 में उत्तर प्रदेश के इटावा से और 1996 में पंजाब के होशियारपुर से सांसद के रूप में सेवा दी तथा इसके बाद राज्यसभा में भी अपनी सेवाएं दीं। नेता की विरासत को सम्मान देने के लिए हाल में उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा, हाल ही में अपने कैबिनेट सहयोगी हरजोत सिंह बैंस के साथ मैंने बाबू कांशीराम जी से जुड़े रोपड़ जिले के गांव ख्वासपुरा और आनंदपुर साहिब के पृथीपुर बुंगा का दौरा किया। उनकी विरासत को स्थानीय स्तर पर सम्मान देने के लिए पंजाब सरकार ने एक स्थानीय स्कूल के पुनर्निर्माण और उन्नयन के लिए 2 करोड़ रुपये की अनुदान राशि स्वीकृत की है, जिसका नाम बाबू कांशी राम जी के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने उनके पैतृक गांव में एक उच्च स्तरीय पुस्तकालय और एक आधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण को भी मंजूरी दी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके ऐतिहासिक योगदान को सुरक्षित रखा जा सके।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आगे कहा, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 2016 में ही औपचारिक रूप से बाबू कांशी राम जी को भारत रत्न देने की मांग की थी। हालांकि इससे पहले 9 अक्टूबर 2006 को बाबू कांशीराम जी के निधन के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बहुजन समाज पार्टी और उनके समर्थकों की व्यापक मांग के बावजूद दिल्ली में उनके लिए एक स्मारक हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करने में विफल रही थी।

अंत में उन्होंने सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव का समर्थन करने की अपील करते हुए कहा, इस सदन को यह प्रस्ताव पूर्ण एकता के साथ पारित करना चाहिए और बाबू कांशी राम जी को भारत रत्न प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार को एक मजबूत सिफारिश भेजनी चाहिए।

ट्रंप का नाटो को कड़ा अल्टीमेटम: होर्मुज की सुरक्षा करो या बुरे भविष्य के लिए तैयार रहो

ट्रंप की दो-टूक- यूक्रेन में हमने मदद की, अब होर्मुज में नाटो चुकाए अपना कर्ज

एजेंसी (हि.स.)

वाशिंगटन/टोक्यो

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में मदद नहीं करते तो उनका भविष्य बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने इस रणनीतिक जलमार्ग को लेकर यूरोपीय देशों को एक कड़ा संदेश दिया।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स को रविवार को फोन पर दिए साक्षात्कार में कहा, यह बिल्कुल सही है कि जो लोग इस जलडमरूमध्य से फायदा उठाते हैं, वे यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि वहां कुछ भी बुरा न हो। उन्होंने कहा, अगर कोई जवाब नहीं आता है तो मुझे लगता है कि यह नाटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा।

राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका से दी गई

ट्रंप ने होर्मुज जलमार्ग को लेकर नाटो और ब्रिटेन को घेरा

मदद का जिक्र करते हुए कहा, हमें यूक्रेन के मामले में उनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं थी।अब हम देखेंगे कि क्या वे हमारी मदद करते हैं। मैं लंबे समय से कहता आ रहा हूं कि हम उनके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें नाटो से किस तरह की मदद चाहिए? राष्ट्रपति ने कहा, जो भी जरूरी हो। उसमें बारूदी सुरंग नष्ट करने वाले जहाज भी शामिल हो सकते हैं। नाटो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी रक्षा गठबंधन है। इसे शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद किसी ऐसे देश की मदद करना नहीं है, जब कोई सदस्य देश खुद ही युद्ध शुरू

फोटोः हि.स.

कर दे। फ्लोरिडा से एयर फोर्स वन विमान से व्हाइट हाउस लौटते समय ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया, हम हमेशा नाटो के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा देश एक बहुत ही छोटे से काम में हमारी मदद नहीं करता।

राष्ट्रपति ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के प्रति अपनी नाराजगी एक बार फिर जहिर की। उनकी नाराजगी का कारण यह था रहा स्टारमर ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों को तुरंत अपना समर्थन नहीं दिया था। उन्होंने कहा, ब्रिटेन को शायद हमारा सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी माना जाता है। जब मैंने उनसे मदद मांगी तो वह साथ नहीं आए।

इस मसले पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने सोमवार को कहा कि जापान की अभी होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में मदद के लिए जहाज भेजने की कोई योजना नहीं है। यह बात प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने सोमवार को कही। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से मदद का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने टोक्यो से सीधा कोई अनुरोध नहीं किया है। बावजूद इसके उनकी सरकार जरूरी कदम उठाने के तरीकों पर विचार कर रही है। उल्लेखनीय है कि ताकाइची और ट्रंप गुरुवार को वाशिंगटन में मिलने वाले हैं।

वर्तमान में नाटो में कुल 32 सदस्य देश हैं। इस सैन्य गठबंधन का सबसे नया सदस्य स्वीडन है। संस्थापक सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

ईरान ने पहली बार इजराइल पर दागी सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल

कहा- अमेरिका से युद्धविराम की पेशकश नहीं की

फोटोः हि.स.

एजेंसी (हि.स.)

तेहरान

अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध का आज 17वां दिन है। ईरान ने रविवार को इस लड़ाई में पहली बार इजराइल पर 'सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल' से हमला किया। यह जानकारी ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की न्यूज एजेंसी तसनीम ने दी। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कल कहा कि ईरान ने न तो युद्धविराम की मांग की है और न ही अमेरिका से बातचीत की पेशकश की है। जब तक जरूरत होगी ईरान अपनी रक्षा करता रहेगा।

आईआरजीसी ने कहा कि सेजिल के माध्यम से इजराइल के सैन्य और रक्षा सुविधा को निशाना बनाया गया है। यह मिसाइल 2000-2500 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। 28 फरवरी को अमेरिका-इजराइल के आक्रमक युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब सेजिल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। आईआरजीसी जनसंपर्क कार्यालय के अनुसार, इस हमले के दौरान अन्य मिसाइलों का भी प्रयोग किया गया। 28 फरवरी के हमलों में पूरे ईरान में सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ और बुनियादी ढांचे को व्यापक क्षति पहुंची है। इसके जवाब में ईरानी सशस्त्र बलों ने युद्ध शुरू किया है। वहीं, अमेरिकी न्यूज चैनल सीबीएस न्यूज को दिए साक्षात्कार में ईरान के विदेशमंत्री अब्बास अराघची ने कल कहा कि ईरान ने न तो युद्धविराम की मांग की है और न ही अमेरिका से बातचीत की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जरूरत होगी तो ईरान खुद की रक्षा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि ईरान इस संघर्ष में पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह स्वीकार करना होगा कि यह युद्ध न्यायसंगत नहीं है। जब तक वह स्वीकार नहीं करते, तब तक ईरान जवाब देता रहेगा।

अराघची ने कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद देश की परमाणु सामग्री जमीन के नीचे दब गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस सामग्री को शायद निकाला जा सके, लेकिन अभी यह पहुंच से बाहर है। ईरान की फिलहाल इसे वापस निकालने की कोई योजना नहीं है। अराघची ने कहा कि हालिया तनाव बढ़ने से पहले, अमेरिका के साथ बातचीत के दौरान ईरान अपनी अत्यधिक समृद्ध सामग्री के भंडार को कम करने के लिए पहले तैयार था।

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तीसरे हफ्ते युद्ध की ज्वाला हुई और तेज

एजेंसी (हि.स.)

तेहरान

फोटोः हि.स.

अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग की ज्वाला तीसरे हफ्ते और अधिक तेज हो गई है।ईरान ने कुवैत, तुर्किए और यूएई में कई ठिकानों पर हमले किए हैं।इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन दागे हैं।ईरान ने दावा किया है कि उसने चार अमेरिकी एयरबेस पर एकीकृत मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इजराइल ने कहा है कि उसकी सेना ने दक्षिणी लेबनान कई स्थानों पर हमला किया है।

अल जजीरा की रिपोर्ट में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के हवाले से कहा गया है कि उसके नौसेना बलों ने रविवार आधीरात बाद भोर होने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के एयरबेस पर चार बार समन्वित मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हमले में अमेरिकी बलों से जुड़े कमांड सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और वायु रक्षा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। ईरानी बल आईआरजीसी ने दावा किया कि सैटेलाइट तस्वीरों में निशाना बनाए गए ठिकानों को भारी नुकसान दिखाई दिया है।

इस बीच, लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एनएनए के अनुसार, इजराइली युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान में हमलों की बौछार की है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने नबातीह जिले के जबदीन शहर को निशाना बनाया। हनिन, कफर, ऐता अल-शाब और यातेर में भी हमलों की खबरें आईं।इससे पहले, आईडीएफ ने एक्स पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका में मिशिगन के सिनेगॉग (यहूदी प्रार्थना स्थल) पर हमले के पीछे जिस व्यक्ति का हाथ था, उसका भाई हिजबुल्लाह में एक कमांडर था।इब्राहिम पिछले सप्ताह इजराइली वायुसेना के हिजबुल्लाह के एक सैन्य ठिकाने पर किए गए हवाई हमले में मारा जा चुका है।

अमेरिका ने 'होर्मुज' संकट पर ब्रिटेन से बात की

लंदन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर से होर्मुज जलडमरूमध्य की मौजूदा स्थिति पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता के अनुसार, स्टार्मर और ट्रंप ने रविवार को इस वैश्विक संकट पर बातचीत के दौरान गंभीर चिंता जताई। एबीसी न्यूज के अनुसार, प्रवक्ता ने कहा, दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व में चल रही स्थिति और तेल के आवागमन में आ रही रुकावट को खत्म करने के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के महत्व पर चर्चा की। इस रुकावट के कारण दुनिया भर में तेल की कीमत बढ़ रही है। प्रवक्ता के अनुसार, प्रधानमंत्री स्टार्मर ने उन अमेरिकी सैनिकों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की, जिन्होंने इस संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवाई है। प्रवक्ता ने बताया कि दोनों नेता एक-दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमत हुए। इसके फौरन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से बात की और मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ब्रिटेन समेत अन्य देशों से अपील की कि वे होर्मुज जलडमरूमध्य में गहराते संकट को सुलझाने में आगे आकर मदद करें।

मणिपुर में अवैध हथियार, मादक पदार्थ एवं चोरी की घटनाओं में शामिल तीन अपराधी गिरफ्तार

एजेंसी (हि.स.)

इंफाल

मणिपुर पुलिस ने राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों से विभिन्न अपराधों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस कड़ी में अवैध हथियार, मादक पदार्थ एवं बैंक में चोरी करते एक चोर को गिरफ्तार किया है।

मणिपुर पुलिस ने सोमवार को बताया कि रविवार को सुरक्षा बलों ने मोरेह स्थित यूको बैंक की इमारत के अंदर से किशन चौहान (29) व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति मोरेह के नगामखाई वेंग स्थित मोरेह बस पार्किंग का निवासी बताया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति ने बैंक में सेंध लगाई थी और एसी, साउंड बॉक्स उपकरण, इलेक्ट्रिक बैटरी आदि चुराने की कोशिश की थी। पूर्व में चोरी किए गए एक ऑडियो साउंड बॉक्स और एक एसी को पुलिस ने उसके पास से बरामद किया है। इसी कड़ी में, सुरक्षा बलों ने खुमान लम्पक स्पोर्ट्स

फोटोः हि.स.

कॉम्प्लेक्स से हेफाजुद्दीन मयांगमयूम (42) को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति इंफाल पश्चिम जिले के कोमलाखोंग माखा लेइकाई का रहने वाला बताया गया है। उसके पास से 1.002 किलोग्राम प्रतिबंधित अफीम बरामद हुई।इसके साथ ही एक मोबाइल फोन, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड भी जब्त किया है। एक अन्य अभियान में इंफाल पश्चिम जिले के लैम्पफेल पुलिस थानांतर्गत लाइफाम खुनौ मयाई लेइकाई से, सगोलशेम बोइचा सिंह (42) उर्फ तायई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति इंफाल पूर्व जिले के सावोमबुंग गेट का निवासी बताया गया है। उसके पास से अवैध हथियार और गोला-बारूद बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक .32 पिस्तौल (दो मैगजीन और 10 राउंड के साथ), मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद किया गया है।

उल्लेखनीय है कि, सुरक्षा बल विभिन्न जिलों के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में तलाशी अभियान और 'एरिया डोमिनेशन' (क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने) की कार्रवाई लगातार जारी रखे हुए हैं। मणिपुर के विभिन्न जिलों में, चाहे वे पहाड़ी क्षेत्र हों या घाटी में रविवार को कुल 115 नाके एवं चेक पॉइंट स्थापित किए गए थे ताकि इलाके में शांति बनी रहे एवं वाहनों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो, हालांकि, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया।

संक्षिप्त-समाचार

सोना और चांदी की कीमत में मामूली गिरावट

नई दिल्ली। घरेलू सरार्फा बाजार में आज शुरूआती कारोबार के दौरान सांकेतिक कमजोरी नजर आ रही है। कीमत में आई गिरावट के कारण देश के ज्यादातर सरार्फा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,59,650 रुपये से लेकर 1,59,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना आज 1,46,340 रुपये से लेकर 1,46,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में भी कमजोरी आने के कारण ये चमकीली धातु आज दिल्ली सरार्फा बाजार में 2,74,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर बिक रही है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 1,59,800 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,490 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,59,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,390 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,59,650 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,46,340 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। इसी तरह कोलकाता में 24 कैरेट सोना 1,59,650 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,46,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,46,390 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

सब्सक्रिप्शन के लिए खुला जीएसपी क्रॉप साइंस का आईपीओ, 24 को हो सकती है लिस्टिंग

नई दिल्ली। एग्रोकेमिकल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी जीएसपी क्रॉप साइंस का 400 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में 18 मार्च तक बोली लगाई जा सकती है। इश्यू की क्लोजिंग के बाद 20 मार्च को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 23 मार्च को अलॉटेड शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 24 मार्च को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 304 रुपये से लेकर 320 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 46 शेयर का है। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स कम से कम 1 लॉट यानी 46 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,720 रुपये का निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इनवेस्टर 1,91,360 रुपये के निवेश से अधिकतम 13 लॉट में 598 शेयर के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत 10 रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 1.25 शेयर जारी हो रहे हैं। इनमें 240 करोड़ रुपये के 75 लाख नए शेयर और 160 करोड़ रुपये के 50 लाख शेयर ऑफर फॉर सेल विंडो के जरिये बेचे जा रहे हैं। इस आईपीओ में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व किया गया है। इसके अलावा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए न्यूनतम 35 प्रतिशत हिस्सा और नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (एनआईआई) के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। इस इश्यू के लिए इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर बनाया गया है, जबकि एमयूजीएफ इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास जमा कराए गए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में किए गए दावे के मुताबिक इसकी वित्तीय सेहत लगातार मजबूत हुई है।

ड्रोन हमले के बाद दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बंद, काठमांडू से सभी उड़ानें रद्द

काठमांडू। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा बंद होने के बाद काठमांडू से दुबई की ओर उड़ान भरने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। नेपाल की सभी एयरलाइन ने यात्रियों से हवाईअड्डा न आने और अपनी टिकट संबंधी व्यवस्था एयरलाइंस की वेबसाइट के माध्यम से करने का अनुरोध किया है। अमेरिकाझइजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद 28 फरवरी से दुबई हवाईअड्डा छह दिनों तक बंद रहा था। इस दौरान भी काठमांडू से दुबई सहित सभी खाड़ी देशों की उड़ाने स्थगित कर दी थी। युद्ध शुरू होने के बाद खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ गई हैं। विशेष रूप से खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी कूटनीतिक मिशनों और सैन्य अड्डों के साथ-साथ तेल अवसंरचना, बंदरगाहों, हवाईअड्डों, होटलों तथा आवासीय और कार्यालय भवनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास सोमवार को हुए ड्रोन हमले के कारण एक ईंधन टैंक में आग लग गई। इसके बाद यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हवाईअड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दुबई से सोमवार को काठमांडू के लिए फ्लाई दुबई, नेपाल एयरलाइंस और हिमालय एयरलाइंस की उड़ानें निर्धारित थीं। इसके साथ ही काठमांडू से दुबई की ओर उड़ान भरने वाले फ्लाई दुबई, एमिरेट्स, हिमालय एयरलाइंस और नेपाल एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें स्थगित कर दी हैं।

जेन-जी आंदोलन की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग को लेकर काठमांडू में प्रदर्शन

काठमांडू। नेपाल में जेन-जी आंदोलन की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करते हुए सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के मैतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन किया। गौरी बहादुर कार्की के नेतृत्व में गठित आयोग ने आंदोलन की जांच पूरी करने के बाद पहले ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। सरकार ने रविवार को ही कैबिनेट बैठक से इस रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया है और संभवतः आज सोमवार को इसके सार्वजनिक होने की संभावना है। आज का यह प्रदर्शन जेन-जी मूवमेंट एलायंस नेपाल, नेपाल जेन-जी फ्रंट और जेन-जी सिविक फोरम के संयुक्त आयोजन में किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही रक्षा बम ने कहा कि जब तक सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करती है, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा।प्रदर्शन के दौरान संगठनों ने सरकार से तुरंत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आंदोलन से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की।

शुरूआती कारोबार में शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

घरेलू शेयर बाजार में आज शुरूआती कारोबार के दौरान मजबूती का रुख नजर आ रहा है। आज के कारोबार की शुरूआत गिरावट के साथ हुई थी। बाजार खुलते ही बिकवाली का दबाव बनने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की कमजोरी और बढ़ गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद खरीदारों ने लिवाली का जोर बना दिया, जिससे ये दोनों सूचकांक रिकवरी कर हरे निशान में पहुंचने में सफल रहे। सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 0.05 प्रतिशत और निफ्टी 0.17 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। प्रातः 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद स्टॉक मार्केट के दिग्गज शेयरों में से ग्रासिम इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इंटरग्लोब एवियशन और

टाटा स्टील के शेयर 2.47 प्रतिशत से लेकर 1.38 प्रतिशत की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। दूसरी ओर, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, ओएनजीसी, मैक्स हेल्थकेयर और डॉ रेड्डीज लेबोरेट्रीज के शेयर 1.63 प्रतिशत से लेकर 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे थे।

अभी तक के कारोबार में स्टॉक मार्केट में 2,045 शेयरों में एक्टिव ट्रेडिंग हो रही थी। इनमें से 882 शेयर मुनाफा कमा कर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जबकि 1,163 शेयर नुकसान उठा कर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। इसी तरह सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से 20 शेयर लिवाली के सपोर्ट से हरे निशान में बने हुए थे। दूसरी ओर 10 शेयर बिकवाली के दबाव में लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जबकि निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 32 शेयर हरे निशान में और 18 शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे थे।

बीएसई का सेंसेक्स आज 148.13 अंक की कमजोरी के साथ 74,415.79 अंक के स्तर पर खुला। कारोबार की शुरूआत होते ही पहले पांच मिनट में ही बिकवाली का दबाव बनने के कारण यह सूचकांक गिर कर 74,384.61 अंक के स्तर तक आ गया। इसके बाद बाजार में खरीदारी शुरू हो गई, जिससे इस सूचकांक की चाल में तेजी आ गई। बाजार में लगातार जारी खरीद बिक्री के बीच सुबह 10 बजे तक का कारोबार होने के बाद सेंसेक्स 38.93 अंक की बढ़त के साथ 74,602.85 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था।

इंफाल पूर्वी जिले से प्रीपाक का कैडर गिरफ्तार

इंफाल (मणिपुर)। राज्य के संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाते हुए सुरक्षा बल के द्वारा लगातार उग्रवादियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में इंफाल पूर्वी जिले में चलाए गये एक अभियान के दौरान प्रतिबंधित संगठन प्रीपाक के एक कैडर को गिरफ्तार किया गया है। मणिपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा सोमवार को जारी बयान में बताया कि रविवार को सुरक्षा बलों ने इंफाल पूर्वी जिले के लामलाई थानांतर्गत सॉओम्बुंग खुनजाओ क्षेत्र से प्रीपाक के एक सक्रिय कैडर को गिरफ्तार किया गया है। कैडर की पहचान अंगोम सना मीतेई उर्फ श्यामचंद (58) के रूप में की गयी है। कैडर मूल रूप से विष्णुपुर जिलांतर्गत तोरबुंग सबल लीकाई का रहने वाला बताया गया है। पुलिस आरोपित से आगे की पूछताछ जारी रखे हुए है।

ग्लोबल मार्केट से कमजोरी के संकेत एशिया में मिला-जुला कारोबार

एजेंसी (हि.स.)

नई दिल्ली

ग्लोबल मार्केट से आज कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। वहीं एशियाई बाजार में भी आज मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है।

पश्चिम एशिया में जारी संकट की वजह से अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान लगातार दबाव बना रखा, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। एस एंड पी 500 इंडेक्स 0.61 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 6,632.19 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह नैस्डेक ने 206.62 अंक यानी 0.93 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,105.36 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। हालांकि डाउ जॉन्स फ्यूचर्स आज फिलहाल 154.02 अंक यानी 0.33 प्रतिशत की तेजी के साथ 46,712.49 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।

यूरोपीय बाजार में भी पिछले सत्र के दौरान कमजोरी का रुख बना रहा। एफटीएसई इंडेक्स 0.43 प्रतिशत टूट कर 10,261.15 अंक के स्तर पर बंद हुआ। इसी तरह सीएसी इंडेक्स ने 0.92 प्रतिशत लुढ़क कर 7,911.53 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके अलावा डीएएक्स इंडेक्स 142.36 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,447.29 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

भारत और साइप्रस की ब्रसेल्स में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा

एजेंसी (हि.स.)

ब्रसेल्स (बेल्जियम)

फोटोः हि.स.

भारत के विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर और साइप्रस के विदेशमंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस की यहां महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। जयशंकर ने एक्स हैंडल पर एक तस्वीर जारी करते हुए कहा कि आज ब्रसेल्स में साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से मिलकर बहुत खुशी हुई।

उन्होंने एक्स पर लिखा, " हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। यूरोपीय संघ और भारत के बीच जुड़ाव को आगे बढ़ाने में साइप्रस के सहयोग की हम सराहना करते हैं।"

विदेशमंत्री जयशंकर ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के विदेशमंत्रियों के साथ वार्ता के लिए रविवार को ब्रसेल्स का दो दिवसीय दौरा शुरू किया। जनवरी में दोनों पक्षों के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर मुहर लगने के बाद भारत की ओर से ब्रसेल्स का यह पहला उच्चस्तरीय दौरा है। ब्रसेल्स में ईयू का मुख्यालय है।

जयशंकर यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काजा कैलास के निमंत्रण पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे हैं। यूरोपीय संघ के 27 देश सदस्य हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान जयशंकर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और बेल्जियम तथा अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे।

तबादला — चुनाव घोषणा के कुछ घंटों बाद ही तबादले

पश्चिम बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

एजेंसी (हि.स.)

कोलकाता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को उनके पदों से हटा दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक दोनों अधिकारी किसी भी चुनाव संबंधी कार्य में शामिल नहीं हो सकेंगे।

निर्वाचन आयोग ने नंदिनी चक्रवर्ती की जगह 1993 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी दुश्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं, 1997 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघमित्रा घोष को राज्य का नया गृह सचिव बनाया गया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को सोमवार दोपहर तीन बजे तक कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है। आयोग ने

मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा हटाए गए

फोटोः हि.स.

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कार्यक्रम रविवार को घोषित किया था और उसके कुछ घंटों के भीतर यह प्रशासनिक बदलाव कर दिया गया। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग को प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग पहले भी चुनाव के दौरान राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में बदलाव करता रहा है। चुनाव से पहले पुलिस अधीक्षक और कोलकाता पुलिस आयुक्त तक को बदले जाने के उदाहरण मौजूद हैं। गृह सचिव स्तर पर भी पहले परिवर्तन हुए हैं, हालांकि मुख्य सचिव स्तर पर हाल के वर्षों में इस तरह का बदलाव दुर्लभ माना जा रहा है। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य को भी पद से हटा दिया गया था। उस समय आयोग ने आरोप लगाया था कि उनके कुछ कदम चुनाव आयोग के निदेशों के अनुरूप नहीं थे। उसी चुनाव के दौरान सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात राजीव कुमार को भी उनके दायित्व से हटाया गया था। नए मुख्य सचिव दुश्मंत नारियाला इससे पहले राज्य के उत्तर बंगाल विकास विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली है। इसके अलावा वह सिंचाई विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी देख चुके हैं।

नई गृह सचिव बनीं संघमित्रा घोष इससे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रधान सचिव रही हैं। इस पद पर रहते हुए उन्होंने राज्य की महिला और बाल कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा विभिन्न सामाजिक योजनाओं के प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभाली। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए इस बार दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को 152 सीटों पर और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 सीटों पर होगा। मतगणना चार मई को की जाएगी।

यानिक सिनर ने जीता अपना पहला इंडियन वेल्स 2026 का खिताब

जोकोविच-फेडरर के खास क्लब में शामिल

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

कैलिफोर्निया में रविवार को खेले गए प्रतिष्ठित इंडियन वेल्स 2026 टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में इटली के स्टार खिलाड़ी यानिक सिनर ने रूस के दानिल मेदवेदेव को 7-6(6), 7-6(4) से हराकर अपना पहला इंडियन वेल्स खिताब जीत लिया। कैलिफोर्निया के रेगिस्तानी मौसम में खेले गए इस मुकाबले में सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा। उन्होंने मैच के दौरान 28 विनर्स और 10 ऐस लगाए तथा नेट पर खेले गए सभी आठ अंकों में सफलता हासिल की।

इस जीत के साथ सिनर इतिहास में ऐसे तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने सभी छह एटीपी मास्टर्स 1000 हार्ड-कोर्ट खिताब जीते हैं। इस उपलब्धि के साथ वह टेनिस के दिग्गज नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर के विशेष क्लब में शामिल हो गए। साल का यह उनका पहला खिताब है। इसके साथ ही वह 1990 के बाद पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने लगातार दो मास्टर्स 1000 खिताब बिना एक भी सेट गंवाए जीते हैं। पेरिस में पिछले वर्ष जीते खिताब से शुरू हुई उनकी जीत की लय इस श्रेणी में 11 मैचों तक पहुंच गई है। पहला सेट काफी रोमांचक रहा। मेदवेदेव ने आक्रामक शुरूआत करते हुए सिनर पर लगातार दबाव बनाया और स्कोर 6-5 तक पहुंचाया, लेकिन सिनर ने वापसी करते हुए मुकाबले को टाईब्रेक तक पहुंचा दिया। टाईब्रेक में इतालवी खिलाड़ी ज्यादा सटीक साबित हुए और 7-6(6) से पहला सेट अपने नाम कर लिया।

दूसरे सेट में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। सिनर ने पांचवें गेम में बिना कोई अंक गंवाए ब्रेक लेकर 3-2 की बढ़त बनाई, लेकिन मेदवेदेव ने हार नहीं मानी और स्कोर 6-6 कर दिया, जिससे मैच एक और टाईब्रेक में पहुंच गया। टाईब्रेक में मेदवेदेव ने 4-0 की बढ़त बना ली थी, लेकिन सिनर ने शानदार वापसी करते हुए लगातार अंक हासिल किए और 7-4 से टाईब्रेक जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। मैच के बाद सिनर ने कहा, मैं लगातार विश्वास बनाए रखता रहा और अपने शॉट्स खेलने की कोशिश करता रहा। अगर तीसरा सेट होता तो मुकाबला बराबरी से शुरू होता, इसलिए मैंने मैच खत्म करने की पूरी कोशिश की और इस जीत से बेहद खुश हूं।

मेदवेदेव का शानदार सफर

मेदवेदेव ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। सेमीफाइनल में उन्होंने विश्व नंबर-1 कार्लोस अल्काराज को हराकर बड़ा उलटफेर किया था और ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन की सीजन की 16 मैचों की जीत की लय को भी तोड़ दिया था। हालांकि, इंडियन वेल्स में यह उनका तीसरा फाइनल था और उन्हें एक बार फिर उपविजेता से संतोष करना पड़ा।

नॉर्थ जोन ने जीता आईडीसीए 7वीं वनडे नेशनल जोनल डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब

एजेंसी (हि.स.)
इंदौर

फोटोः हि.स.

इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन (आईडीसीए) द्वारा आयोजित 7वीं वनडे नेशनल जोनल डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का रविवार को समापन इंदौर में हुआ, जिसमें रोमांचक मुकाबलों के बाद नॉर्थ जोन ने खिताब अपने नाम किया, जबकि साउथ जोन उपविजेता रहा। प्रतियोगिता में देश के पांच जोन की डेफ पुरुष टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24.1 ओवर में 120 रन बनाए। टीम की ओर से कुलदीप सिंह ने 31 रन की अहम पारी खेली। साउथ जोन की तरफ से यशवंत नायडू ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट हासिल किए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ जोन ने 25.5 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 127 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। टीम की जीत में वैभव ने 42 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि रोहित सैनी ने गेंदबाजी में पांच विकेट लेकर अहम योगदान दिया। चैंपियनशिप के अन्य मुकाबलों में सेंट्रल जोन ने ईस्ट जोन को 55 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट्रल जोन ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 187 रन बनाए, जिसमें विराज कोल्टे ने 30 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में ईस्ट जोन की टीम 18.1 ओवर में 132 रन पर सिमट गई। संजू शर्मा ने तीन विकेट लेकर सेंट्रल जोन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि संतोष कुमार मोहापात्रा ने 34 रन बनाए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉ. अतुल मलिकराम ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की, जबकि विशिष्ट अतिथि राखाल कुमार सेठी ने उपविजेता टीम को सम्मानित किया। आईडीसीए के अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा कि इस चैंपियनशिप ने डेफ क्रिकेटरों की प्रतिभा और खेल के प्रति उनके समर्पण को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

यह प्रतियोगिता 11 से 15 मार्च 2026 तक इंदौर स्थित द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें देशभर के डेफ क्रिकेटरों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

व्यक्तिगत पुरस्कारः

मैन ऑफ द मैचः विवेक कुमार (नॉर्थ जोन), अमन चौकसे (सेंट्रल जोन)
सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजः अभिषेक सिंह (ईस्ट जोन)
सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजः विवेक कुमार (नॉर्थ जोन)
प्लेयर ऑफ द सीरीजः विवेक कुमार (नॉर्थ जोन)

दक्षिण अफ्रीका सीरीज से बाहर हुए ईश सोढ़ी

एजेंसी (हि.स.)
माउंट माउंगानुई

फोटोः हि.स.

न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर ईश सोढ़ी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। प्रशिक्षण सत्र के दौरान गेंदबाजी करते समय उनके अंगूठे में चोट लग गई थी और स्कैन में अंगूठा टूटने की पुष्टि हुई है। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें पूरी तरह ठीक होने में करीब चार सप्ताह का समय लगेगा।

टीम प्रबंधन के अनुसार, चोट के कारण सोढ़ी सीरीज के शेष मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रहेंगे। इस बीच तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन दूसरे और तीसरे मैच के लिए टीम से जुड़ चुके हैं, जो क्रमशः हैमिल्टन और ऑकलैंड में खेले जाएंगे। चयनकताओं ने सोढ़ी की जगह किसी नए खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया है। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी अब मिचेल सैंटनर और कोल मैककॉन्ची संभालेंगे। न्यूजीलैंड टीम के मुख्य कोच रॉब वॉल्टर ने कहा, ईश न्यूजीलैंड के लिए खेलने को लेकर बेहद उत्साहित रहते हैं और विश्व कप अभियान के बाद घरेलू दर्शकों के सामने खेलने के लिए भी वे काफी उत्सुक थे। टी20 प्रारूप में उनका अनुभव टीम के लिए बहुत अहम है, इसलिए उनका बाहर होना निश्चित रूप से बड़ा नुकसान है। उन्होंने आगे कहा कि टीम को भरोसा है कि फर्ग्यूसन के जुड़ने के साथ-साथ सैंटनर और मैककॉन्ची अगले मुकाबलों में टीम की जरूरतों को पूरा करेंगे। सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए काटेने क्लार्क, डेन क्लीवर, जेडन लेनॉक्स और टॉम लैथम टीम से जुड़ेंगे। इन मैचों में कप्तानी की जिम्मेदारी भी लैथम संभालेंगे, जो सैंटनर की जगह टीम की अगुवाई करेंगे। गौरतलब है कि सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम मात्र 91 रन पर सिमट गई थी और दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच आसानी से अपने नाम कर लिया।

एथलीट-फर्स्ट गवर्नेंस भारतीय खेलों के भविष्य का मार्गदर्शन करेगीः पीटी उषा

एजेंसी (हि.स.)
नई दिल्ली

फोटोः हि.स.

भारतीय ओलम्पिक संघ (आईओए) अध्यक्ष पीटी ऊषा ने भारतीय खेलों में एथलीट-केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र का भविष्य ऐसी नीतियों से तय होना चाहिए जिनमें खिलाड़ियों को निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में रखा जाए।

आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा ने रविवार को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजेएफआई) के स्वर्ण जयंती राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की तैयारी, कल्याण और विकास खेल प्रशासकों तथा खेल संस्थाओं की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन (डीएसजेए) कर रहा है। पीटी उषा ने कहा, एथलीट-फर्स्ट गवर्नेंस भारतीय खेलों के भविष्य का मार्गदर्शन करनी चाहिए। खिलाड़ियों की तैयारी, उनका कल्याण और विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। भारतीय खेलों के बदलते परिदृश्य पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश इस समय अपने खेल सफर के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। बेहतर बुनियादी ढांचा, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन के कारण भारतीय खिलाड़ी अब वैश्विक मंच पर अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिछले एक दशक में हमने देखा है कि देश में खेलों को समर्थन और सम्मान देने के तरीके में बड़ा बदलाव आया है।

आज खिलाड़ियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और मजबूत संस्थागत समर्थन मिल रहा है। पीटी उषा ने जमीनी स्तर पर खेलों के विकास के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय खेलों की असली ताकत गांवों, कस्बों और स्कूलों में छिपी हुई प्रतिभाओं में है, जिन्हें पहचानने और आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, भारतीय खेलों की असली ताकत जमीनी स्तर पर है—गांवों, कस्बों और स्कूलों में जहां नई प्रतिभाएं सामने आने का इंतजार कर रही हैं। यदि हम कोचिंग, बुनियादी ढांचे और प्रतिभा पहचान में लगातार निवेश करते रहें, तो भारत लगातार विश्वस्तरीय खिलाड़ी तैयार कर सकता है। पीटी उषा ने खेल पत्रकारिता की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि खेल पत्रकार केवल परिणाम बताने वाले नहीं होते, बल्कि वे खिलाड़ियों के संघर्ष, भावनाओं और उपलब्धियों की कहानियों को सामने लाते हैं। जिम्मेदार और गहन खेल पत्रकारिता देश में खेलों की मजबूत नींव तैयार करती है। सम्मेलन के दौरान आयोजित एक पैनल चर्चा में आईओए के सीईओ रघुराम अय्यर ने कहा कि भारत इस समय अपने खेल विकास के एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है, जहां बढ़ती महत्वाकांक्षा, निवेश और भागीदारी देश को एक प्रमुख खेल राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि भारत खेलों में इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हमारे पास महत्वाकांक्षा है और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। अय्यर ने कहा कि खेलों में भारत की प्रगति को बनाए रखने के लिए मजबूत जमीनी खेल ढांचा तैयार करना बेहद जरूरी है, जिसकी शुरूआत समुदाय स्तर पर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बढ़ाने से होगी।

उन्होंने कहा, हमें ऐसा खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा जिसमें समुदाय स्तर पर अधिक लोग खेलों में भाग लें। जब यह आधार तैयार होगा, तब सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शीर्ष स्तर तक पहुंचने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन दिया जाना चाहिए।

बांग्लादेश के रिव्यू को लेकर पाकिस्तान ने दर्ज कराई आधिकारिक शिकायत

एजेंसी (हि.स.)
मीरपुर

फोटोः हि.स.

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ रविवार को खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान लिए गए विवादित रिव्यू को लेकर मैच रेफरी नेयामुर राशिद से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। यह मामला मीरपुर में खेले गए मुकाबले के आखिरी ओवर से जुड़ा है, जिसमें ऑन-फील्ड अंपायर कुमार धर्मसेना के फैसले पर सवाल उठाए गए हैं।

ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान टीम प्रबंधन का आरोप है कि बांग्लादेश ने आखिरी से दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू का रिव्यू उस समय लिया जब उस गेंद का रिप्ले पहले ही स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जा चुका था। मुकाबले के उस समय पाकिस्तान को जीत के लिए दो गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी। बांग्लादेश के गेंदबाज रिशाद हुसैन ने लेग स्टंप पर फ्लाइटेड गेंद डाली, जो लेग साइड की ओर घूमती हुई बल्लेबाज शाहीन शाह अफरीदी से दूर निकल गई। अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। इसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने आपस में चर्चा की और एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू ले लिया, जबकि पहली नजर में गेंद अफरीदी के शरीर या पैरों के पास भी नहीं दिख रही थी। सामान्य नियमों के अनुसार रिव्यू लेने का फैसला खिलाड़ियों को रिप्ले दिखने से पहले करना होता है, ताकि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली जानकारी से निर्णय प्रभावित न हो। पाकिस्तान का आरोप है कि इस मामले में यह प्रोटोकॉल सही तरीके से नहीं अपनाया गया। उनका यह भी कहना है कि संभव है कि बांग्लादेश ने 15 सेकंड की तय समय-सीमा के बाद रिव्यू लिया हो, हालांकि प्रसारण में कोई टाइमर नहीं दिखाया गया, जिससे इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी।

दर्पण

33वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के तहत सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 173 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 मार्च 2026 है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन करना आवश्यक है।

श्रेणी	पदों की कुल संख्या
अनारक्षित वर्ग	69
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	17
अनुसूचित जाति	28
अनुसूचित जनजाति	2
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	36
पिछड़ा वर्ग	21
कुल	173

कौन कर सकता है आवेदन

आपको LLB (विधि स्नातक) होना चाहिए, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या कॉलेज से हो। यह प्रमाण होना चाहिए कि आपके कॉलेज/विश्वविद्यालय को उस समय बार काउंसिल से मान्यता मिली हुई थी। प्रमाण पत्र कॉलेज/विश्वविद्यालय के प्राचार्य या अधिकारी से होना चाहिए।

क्या है अनुभव की शर्तें

आवेदन की तारीख तक आपको कम से कम 3 साल का वकील का अनुभव होना चाहिए। अनुभव की गिनती आपके राज्य बार में नामांकन की तारीख से होगी। प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र या तो जिला के प्रधान न्यायाधीश से या ऐसे 10 साल के अनुभवी वकील से होना चाहिए, जिसे न्यायालय ने प्रमाणित किया हो। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले उम्मीदवारों का प्रमाण ऐसे अनुभवी वकील से होना चाहिए। विधि क्लर्क के रूप में किया गया काम भी अनुभव में गिना जाएगा।

ऐसे होगा चयन

बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा के तहत चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। हर चरण में सफल होने वाले उम्मीदवार ही अगले चरण के लिए योग्य होंगे। अंतिम चयन पूरी प्रक्रिया और मेरिट लिस्ट के आधार पर तय किया जाएगा। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही और प्रमाणित होनी चाहिए। अगर आवेदन में कोई गलत, अधूरी या त्रुटिपूर्ण जानकारी होगी तो आपका फॉर्म रद्द किया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नए उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करें और अपने ईमेल व मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। इसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सही-सही डालें। जरूरी दस्तावेज जैसे- पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और प्रमाण पत्र अपलोड करें। आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करें। सभी जानकारी सही होने के बाद फॉर्म सबमिट करें। सबमिट करने के बाद फॉर्म की कॉपी और भुगतान रसीद अपने पास सुरक्षित रखें।

झारखंड के अस्पताल में निकली मैनेजर की भर्ती

झारखंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत अस्पताल प्रबंधक पदों की भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। राज्य के मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, उप-मंडल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन पदों के लिए कुल 201 रिक्तियां उपलब्ध हैं। इच्छुक उम्मीदवार 30 मार्च 2026 तक jrhms.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 41,000 रुपये दिए जाएंगे।

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित में से कोई एक शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य हैः अस्पताल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सेवा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अस्पताल प्रबंधन/अस्पताल प्रशासन में एमबीए, या लोक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर (एमपीएच), साथ ही संबंधित क्षेत्र में आवश्यक अनुभव होना चाहिए। साथ ही, उम्मीदवार के पास सार्वजनिक स्वास्थ्य या अस्पताल प्रशासन में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा उद्योग में अनुभव और अस्पताल प्रबंधन का गहन ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर और स्वास्थ्य प्रबंधन सॉफ्टवेयर का अनुभव भी इस पद के लिए जरूरी है।

कैसे होगा चयन

जेआरएचएमएस में उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता, अनुभव और कौशल के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले आवेदनों की जाँच (स्क्रीनिंग) की जाएगी कि उम्मीदवार ने जरूरी योग्यता और अनुभव पूरा किया है या नहीं। अगर किसी उम्मीदवार ने गलत जानकारी दी हो या पात्रता पूरी नहीं की हो, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस भर्ती से जुड़े अंतिम फैसले का अधिकार झारखंड स्वास्थ्य विभाग के पास रहेगा और उसका निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jrhms.jharkhand.gov.in पर जाएं। नई खाता बनाएं (New Registration) और अपनी बुनियादी जानकारी भरें। रजिस्ट्रेशन के बाद अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें। ऑनलाइन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सही-सही भरें। जरूरी दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि अपलोड करें। निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करें। सारी जानकारी ध्यान से चेक करें और फिर फॉर्म को सबमिट करें।

वर्ग	रिक्तियां
जनरल	81
ईडब्ल्यूएस	20
बीसी-आई	20
ईसा पूर्व द्वितीय	16
अनुसूचित जनजाति	52
अनुसूचित जाति	12
कुल	201

एनएचपीसी में निकलीं ट्रेनी इंजीनियर की नौकरियां

एनएचपीसी लिमिटेड ने प्रशिक्षु अभियंता (सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 72 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 16 मार्च 2026 सुबह 10 बजे से 6 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कौन कर सकता है आवेदन

ट्रेनी इंजीनियर (सिविल): उम्मीदवार के पास अक्ऊळए से मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक या बीएससी (इंजीनियरिंग) की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। 31 मई 2013 तक अटक्ए 60% अंकों के साथ पास करने वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं। **ट्रेनी इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल)**: उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक या बीएससी (इंजीनियरिंग) की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए। **ट्रेनी इंजीनियर (मैकेनिकल)**: उम्मीदवार के पास मैकेनिकल, थर्मल, प्रोडक्शन या मैकेनिकल एवं ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में बी.ई./बी.टेक या बीएससी (इंजीनियरिंग) की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए।

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

इस भर्ती के लिए ओबीसी (एनसीएल) वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये + कर मिलाकर कुल 708 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग और पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, यानी वे बिना शुल्क के आवेदन कर सकते हैं।

इतना मिलेगा वेतन

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को ए-2 ग्रेड के तहत 50,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक का वेतनमान दिया जाएगा। शुरूआत में उम्मीदवारों को 1 साल की प्रशिक्षण अवधि पूरी करनी होगी। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 1 साल की परिवीक्षा अवधि होगी। इस पद पर काम करने वाले उम्मीदवारों का अनुमानित वार्षिक उळउ लगभग 15-16 लाख तक हो सकता है।

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले ठऌढउ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। अगर आप नए उम्मीदवार हैं, तो New Registrationf पर क्लिक करके अपनी बेसिक जानकारी भरें और यूजर आईडी और पासवर्ड बनाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सही-सही भरें। यदि आप ओबीसी (एनसीएल) वर्ग के हैं तो ऑनलाइन भुगतान करें। सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।

क्षेत्र में कॉक्लियर इम्प्लांट का नया युग: डॉ. जैमंती बख्शी

पीजीआईएमईआर के कान-नाक-गला एवं हेड-नेक सर्जरी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष का दावा

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

उत्तर भारत में श्रवण स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए, दक्षिण एशिया में प्रारंभिक मामलों में से एक तथा ट्राइसिटी में पहला SMART Nucleus NEXA CI1032 Slim Perimodiolr Cochler Implft सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया। यह सर्जरी प्रमुख कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन डॉ. जैमंती बख्शी, विभागाध्यक्ष, ईएनटी एवं हेड-नेक सर्जरी विभाग और उनकी सर्जन टीम द्वारा की गई। इस टीम में ऑडियोलॉजी एवं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. धर्म वीर और डॉ. नूरैन आलम भी शामिल थे।

यह उपलब्धि क्षेत्र में कॉक्लियर इम्प्लांट की उपलब्धता और उन्नत तकनीक के उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है और श्रवण पुनर्स्थापन (ँ१ल्लॅ श१२३ङ्क१ं३ङ्कल्ल) के क्षेत्र में एक नए युग की शुरूआत का संकेत देती है। बच्चों में सुनने की समस्या अक्सर जीवन के शुरूआती महीनों में अनदेखी रह जाती है, जबकि यही समय भाषण और मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। समय पर पहचान से उपचार जल्दी संभव हो पाता है, जिससे बोलने, भाषा सीखने, शिक्षा और सामाजिक कौशल में होने वाली देरी को रोका जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर हस्तक्षेप केवल लाभदायक ही नहीं बल्कि अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चों को विकास के सही समय पर श्रवण उत्तेजना मिलती है, तो सुनने और बोलने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार होता है और वे मुख्यधारा की शिक्षा और समाज में बेहतर तरीके से शामिल हो पाते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक श्रवण उपकरण है, जिसे गंभीर से अत्यधिक श्रवण हानि वाले उन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है जिन्हें हियरिंग एड से सीमित लाभ मिलता है। हियरिंग एड जहाँ ध्वनि को केवल बढ़ाते हैं, वहीं कॉक्लियर इम्प्लांट भीतरी कान के क्षतिग्रस्त भागों को बायपास कर सीधे श्रवण तंत्रिका को विद्युत संकेतों के माध्यम से उत्तेजित करता है। इन संकेतों को मस्तिष्क ध्वनि के रूप में पहचानता है, जिससे उपयोगकर्ता को बोलचाल और आसपास की ध्वनियों को सुनने में मदद मिलती है। इम्प्लांट में अंतर्निहित मेमोरी, जिसमें MAPs और आवश्यक श्रवण सेटिंग्स सुरक्षित रहती हैं, जिससे SMART Syfc के माध्यम से साउंड प्रोसेसर बदलने या अपग्रेड होने की स्थिति में उपयोगकर्ता जल्दी से पुनः सक्रिय हो सकते हैं ये नवाचार यह सुनिश्चित करते हैं कि उपयोगकताओं को ऐसी तकनीक मिले जो समय के साथ उनकी श्रवण आवश्यकताओं के अनुसार विकसित हो सके। परिवार ने NEXA सिस्टम को इसके भविष्य-उन्मुख डिजाइन, स्मार्ट विशेषताओं और विश्वसनीयता को समझने के बाद चुना। इम्प्लांट में श्रवण सेटिंग्स को सुरक्षित रखने, फर्मवेयर अपग्रेड का समर्थन करने और लगातार बेहतर ध्वनि प्रदर्शन प्रदान करने की क्षमता ने परिवार को यह भरोसा दिया कि बच्चे को आने वाले वर्षों में भी उन्नत श्रवण सहायता मिलती रहेगी। परिवार का निर्णय उपचार टीम के अनुभव और प्रतिष्ठा से भी प्रभावित हुआ। डॉ. जैमंती बख्शी की सर्जिकल विशेषज्ञता और पीजीआईएमईआर के बहु-विषयक कॉक्लियर इम्प्लांट कार्यक्रम के संयोजन से मरीजों को मूल्यांकन से लेकर सर्जरी और पुनर्वास तक व्यापक और समग्र देखभाल उपलब्ध कराई जाती है।

पंजाब के युवाओं को नशे और हिंसा से बचाना जरूरी राज्यसभा में रेखा शर्मा ने उठाया गंभीर मुद्दा

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने आज संसद के उच्च सदन में पंजाब में तेजी से बढ़ती नशे की समस्या तथा फैलते हुए गन कल्चर का गंभीर मुद्दा उठाते हुए इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि पंजाब के युवाओं, सामाजिक संरचना और राज्य के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। सदन में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जालंधर ग्रामीण के मेहतपुर क्षेत्र से एक सप्ताह के भीतर तीन युवाओं की सस्पेक्टेड ड्रग ओवरडोज से मृत्यु की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि ये घटनाएँ इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि जमीनी स्तर पर नशीले पदार्थ कितनी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं और किस प्रकार युवा पीढ़ी इस घातक जाल में फँसती जा रही है। इसके कारण न केवल परिवार बिखर रहे हैं, बल्कि पूरे समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण बन रहा है। रेखा शर्मा ने कहा कि नशे के बढ़ते प्रचलन के साथ-साथ पंजाब में संगठित अपराध और हथियारों से जुड़ी हिंसा की घटनाएँ भी चिंताजनक रूप से बढ़ रही हैं। गैंग प्रतिद्वंद्विता, वसूली के नेटवर्क और टार्गेटेड किलिंग जैसी घटनाएँ आम नागरिकों के मन में भय का माहौल पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएँ यह दशार्ती हैं कि अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और राज्य में गन कल्चर का प्रसार एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। यदि समय रहते इस समस्या पर कठोर और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इसके दूरगामी और गंभीर परिणाम न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही नशे से प्रभावित युवाओं के लिए पुनर्वास और जागरूकता कार्यक्रमों को भी व्यापक स्तर पर मजबूत किया जाए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियाँ मिलकर इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएँगी, ताकि पंजाब के युवाओं को नशे और अपराध के इस दुष्चक्र से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं का सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम द्वारा अर्बन एरिया पंचकूला में की गई बड़ी कार्यवाही

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा के मार्गदर्शन में डीटीपी श्रीमती बबीता गुप्ता के नेतृत्व में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की टीम द्वारा अर्बन एरिया पंचकूला में बड़ी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव बरवाला में लगभग 6 एकड में स्थित अवैध कॉलोनी में तोड़-फोड़ की गई। इस दौरान प्लाटों की निशानदेही व सड़क नेटवर्क को जेसीबी द्वारा धवस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, श्री नरेन्द्र कुमार, एसडीई, पंचायती राज, पंचकूला, श्री अशोक कुमार, सहायक नगर योजनाकर, पंचकूला व श्री डिम्पी राठी, सहायक नगर योजनाकर, पंचकूला एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में संपन्न हुई।

इस संबध में जानकारी देते हुए डीटीपी श्रीमती बबीता गुप्ता ने बताया कि कोई भी निर्माण या कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति से किसी प्रकार का अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित करता पाया गया तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही जारी रखी जाऐगी। उन्होने कहा कि आम जनता से अनुरोध किया गया है कि विभाग से सी.एल.यु/लाईसेंस की अनुमति लिए बिना कोई भी निर्माण व अनाधिकृत कॉलोनी विकसित न करें।

ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता पर कार्यशाला सह ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

ऊर्जा प्रबंधन प्रकोष्ठ / राज्य नामित एजेंसी इंजीनियरिंग विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता विषय पर एक कार्यशाला तथा ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री प्रेरणा पुरी (आईएएस), सचिव, इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ने शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने भवन क्षेत्र में ऊर्जा खपत को कम करने तथा पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सतत निर्माण पद्धतियों और ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने के महत्व पर बल दिया।

इस अवसर पर श्रे सी.बी. ओझा, मुख्य अभियंता, यू.टी. चंडीगढ़ भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है, जिससे भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष प्रथाओं के क्रियान्वयन को और अधिक मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान एक तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें आर्किटेक्ट जित कुमार गुप्ता ने सतत भवन डिजाइन, ऊर्जा दक्ष निर्माण तकनीकों तथा आधुनिक भवनों में ऊर्जा संरक्षण उपायों के समावेशन पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकियों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में जॉनसन टाइल्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, महालक्ष्मी ब्रिक्स, एल.के. इलेक्ट्रिकल तथा विनायक इंडस्ट्री जैसी अग्रणी कंपनियों ने कूल रूफ टाइल्स, हीट-रिफ्लेक्टिव पेंट्स, एएसी ब्लॉक्स सहित अन्य ऊर्जा दक्ष निर्माण सामग्रियों और नवाचार उत्पादों का प्रदर्शन किया। इस कार्यशाला में लगभग 125 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें इंजीनियर, बिल्डर, आर्किटेक्ट तथा विद्यार्थी शामिल थे। प्रतिभागियों ने ऊर्जा संरक्षण तथा सतत निर्माण पद्धतियों से संबंधित विषयों पर सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया।

इंजीनियर पवन शर्मा, ने कार्यक्रम के दौरान इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी, जिनमें ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों का प्रचार-प्रसार, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों का क्रियान्वयन शामिल है।

उपायुक्त ने समाधान शिविर में सुनी जिलावासियों की समस्याएं

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

उपायुक्त ने श्री सतपाल शर्मा ने आज लघु सचिवालय के सभागार में समाधान शिविर में सैक्टर-19 के निवासियों की सीवर ओवरफलो व मलबा बाहर आने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एचएसवीपी के संबंधित अधिकारी को मौके का मुआयना कर सीवर खुलवाने के बाद शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने हरियाणा सरकार द्वारा निर्देशित समाधान शिविर में 6 जिलावासियों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को बिना विलंब के समाधान करने के निर्देश दिए।

उपायुक्त ने बिटना रोड आफिसर कालोनी के लोगों की पेयजल समस्या व पाईप बदलने की मांग पर जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के संबंधित अधिकारी को मौके पर जाकर चैक करने व जल्द से जल्द पेयजल पाईप बदलने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविर में आई शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर बिना विलम्ब किए समाधान करें ताकि जिलावासियों को समय पर जिला प्रशासन की सुविधाएं व सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। शर्मा ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की मंशा है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग सरकारी कार्यालयों में चक्कर न काटने पडे। इसी सोच के अनुरूप मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार हर कार्यदिवस के दिन सोमवार व वीरवार को प्रात 10 बजे से 12 बजे तक समाधान शिविर का आयोजन किया जाता है जंहा सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहते हैं। उन्होने कहा कि समय समय पर मुख्यमंत्री स्वयं वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुडकर लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं पर की गई कारवाई की फीडबैक लेते हैं।

इस अवसर पर नगराधीश जागृति, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी विशाल पराशर, जिला बागवानी अधिकारी अशोक कौशिक, सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन सत्यवान भारद्वाज, सहित जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, एचएसवीपी, पीएमडीए, वन विभाग, आयुष, पुलिस, स्वास्थ्य, सिंचाई, नगर निगम और अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद थे।

हरियाणा में पेट्रोल-डीजल और एल.पी.जी. की नहीं आने देंगे कमी : बन्तो कटारिया

सिटी दर्पण संवाददाता
पंचकूला

हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष बन्तो कटारिया ने कहा की मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समय-समय पर बैठक कर मिडिल ईस्ट में उत्पन्न युद्ध परिस्थितियों के कारण एल.पी.जी.गैस की आपूर्ति बाधित होने संबंधी फैल रही अफवाहों की स्तिथि पर चर्चा की है। बन्तो कटारिया ने बताया कि वर्तमान में पेट्रोल-डीजल और एल.पी.जी.की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं । गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही हैं । हालांकी कमर्शियल गैस की सिलिंडर की आपूर्ति में अस्थाई रूप से बाधा आ रही हैं ।क्योंकि कमर्शियल सिलैंडर प्राथमिकता के आधार पर शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को दिए जा रहें हैं ' बन्तो कटारिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा की लोगों में झूठी अफवाह व भ्रम फैलाना कांग्रेस पार्टी का पुराना काम हैं। हरियाणा की नायब सरकार ने यह सुनिश्चित किया हैं कि घरेलू गैस सिलेंडर की चोरी या कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तो, पुलिस अधीक्षकों और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। बन्तो कटारिया ने आमजन से अपील करी की वे एल.पी.जी. गैस की आपूर्ति को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें एवं भंडारण से बचे क्योंकि राज्य में आवश्यक पैट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हैं व आपूति सुचारू रूप से जारी रहेगी।

संक्षिप्त-समाचार

पीजीआई के हॉर्टिकल्चर विंग ने वसंत उत्सव 2026 में लगातार पाँचवीं बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती

चंडीगढ़। संस्थान के हॉर्टिकल्चर विंग ने 13.03.2026 से 15.03.2026 तक सेक्टर-5, पंचकूला के टाउन पार्क में PMDA द्वारा आयोजित वसंत उत्सव 2026 पुष्प प्रतियोगिता में 34 पुरस्कार जीतकर शीर्ष स्थान हासिल करते हुए पीजीआई का नाम रोशन किया। हॉर्टिकल्चर विंग ने पॉट सेक्शन और कट फ्लावर सेक्शन में कुल 18 प्रथम पुरस्कार, 12 द्वितीय पुरस्कार और 4 तृतीय पुरस्कार प्राप्त किए। विंग ने लगातार पाँचवीं बार ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम की, जो इस शो में किसी भी प्रतिभागी द्वारा किया गया रिकॉर्ड प्रदर्शन है। विभाग ने इस प्रतियोगिता में कुल 34 पुरस्कार और 'ओवरऑल ट्रॉफी' अपने नाम की। विभाग को 'पॉट' (गमला) और 'कट फ्लावर' (कटे हुए फूल) श्रेणियों में 18 प्रथम पुरस्कार, 12 द्वितीय पुरस्कार और 4 तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए। विभाग ने लगातार पाँचवें वर्ष 'ओवरऑल ट्रॉफी' जीती है, जो इस प्रदर्शनी में किसी भी प्रतिभागी द्वारा किया गया एक रिकॉर्ड प्रदर्शन भी है।

आज खंड बरवाला के गांव त्रिलोकपुर में होगा रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन

पंचकूला। ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान हेतु हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के अंतर्गत 17 मार्च को खंड बरवाला के गांव त्रिलोकपुर स्थित ग्रांम सचिवालय में रात्रि ठहराव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा गांव में उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे तथा उनका समाधान करेंगे। कार्यक्रम के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य, डीआरडीए, कृषि, बागवानी, पशुपालन, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी, बिजली और अन्य विभागों सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, एलडीएम पंचकूला द्वारा सूचना एवं सेवा स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों के माध्यम से अधिकारी एवं कर्मचारी ग्रामीणों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे तथा पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान करेंगे। रात्रि ठहराव कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बीईएल पंचकूला ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में दिया 1.1 लाख रुपये का दिया योगदान

पंचकूला। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) पंचकूला की महाप्रबंधक श्रीमती दीपा बाजपेयी ने, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान के रूप में, पंचकूला के उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा को 1,10,400 रुपये का चेक सौंपा। इस अवसर पर राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड, पंचकूला के कल्याण अधिकारी विंग कमांडर संजय के. राय (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित थे। बीईएल-पंचकूला के कर्मचारियों द्वारा दिया गया यह योगदान पूर्व सैनिकों, युद्ध वीरांगनाओं और उनके आश्रितों के कल्याण, पुनर्वास और भलाई के प्रति बीईएल की निरंतर प्रतिबद्धता को दशार्ता है। बीईएल राष्ट्र-निर्माण की पहलों में योगदान देने और ऐसे सार्थक प्रयासों के माध्यम से सशस्त्र बलों के समुदाय का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

चंडीगढ़ ब्यापार मंडल ने एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के नए नियमों का स्वागत किया

चंडीगढ़। चंडीगढ़ ब्यापार मंडल (सीबीएम) ने एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन के नए नियमों का स्वागत किया, जिससे देश भर के व्यापारियों को लाभ होने की उम्मीद है। संजीव चड्ढा, प्रेसिडेंट, चंडीगढ़ ब्यापार मंडल ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन का धन्यवाद किया और कहा कि सीबीएम द्वारा इस मांग को विभिन्न मंचों पर समय-समय पर उठाया गया था और इस नवीनतम सरकारी अधिसूचना के साथ न केवल यह पूरा हुआ है, बल्कि नए नियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनाए गए व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। चरनजीव सिंह, चेयरमैन, सीबीएम, और मेम्बर, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड ने सुनील सिंघी, चेयरमैन, नेशनल ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड को व्यापारिक समुदाय के लिए इस राहत के लिए आभार व्यक्त किया। नए नियमों से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल हो गई है और छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन लागत कम हो गई है। नए टर्नओवर थ्रेशोल्ड हैं: - रजिस्ट्रेशन: टर्नओवर तक रु. 1.5 करोड़ - स्टेट लाइसेंस: टर्नओवर रु. 1.5 करोड़ से ऊपर और रु. 50 करोड़ तक - सेंट्रल लाइसेंस: टर्नओवर रु. 50 करोड़ से ऊपर।

एसडी कॉलेज में यूके-भारत फ्रेंडशिप पर युवा इंटरेक्शन कार्यक्रम आयोजित, मिस इंग्लैंड 2025-26 ग्रेस रिचर्डसन रहीं उपस्थित

मिस इंग्लैंड ने यूथ लीडरशिप और सामाजिक बदलाव पर युवाओं के साथ साझा किए अनुभव

सिटी दर्पण संवाददाता
चंडीगढ़

सेक्टर-32 स्थित गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज में सोमवार को ह्लसेलिब्रेटिंग यूके-इंडिया फ्रेंडशिप: इंटरेक्शन विद मिस इंग्लैंड एंड बोपाह्व विषय पर एक यूथ इंटरेक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 युवा प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने विचार साझा किए। कॉलेज और एनजीओ युवसत्ता के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम ने युवाओं के लिए विचार-विमर्श का एक सशक्त मंच प्रदान किया। इंटरेक्शन के दौरान युवा नेतृत्व, सामाजिक समावेशन, जनस्वास्थ्य जागरूकता तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

कार्यक्रम में मिस इंग्लैंड 2025-26 ग्रेस रिचर्डसन तथा मिस कोवेंट्री और मिस इंग्लैंड फाइनलिस्ट शरनदीप सहोता उपस्थित थे। दोनों अतिथियों की भागीदारी ने भारत-यूके फ्रेंडशिप, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच आपसी संबंधों के महत्व को रेखांकित किया। विशेष रूप से सामाजिक सरोकारों और वैश्विक समझ के प्रति प्रतिबद्ध युवाओं के लिए यह संवाद प्रेरणादायक रहा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवाओं को समाज सेवा, नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. अजय शर्मा ने युवाओं में यूथ लीडरशिप और इंटरनेशनल एक्सपोजर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुभव युवाओं को समाज के प्रति जिम्मेदार, समावेशी और संवेदनशील बनाने में सहायक होते हैं। कार्यक्रम ने युवा प्रतिभाओं को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने और सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा दी।

कार्यक्रम के अवसर पर ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ने एसडी कॉलेज के परिसर का दौरा किया और वहां शिक्षकों व छात्रों के साथ संवाद किया। अतिथियों का स्वागत करने का मार्गदर्शन करने वाली कॉलेज टीम का नेतृत्व गगनप्रीत वालिया ने किया। उनके साथ डॉ. इन्दु मेहता, डीन, और डॉ. सुमिता सिक्का उपस्थित रहीं, जिन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के साथ संवाद को सहज और प्रभावशाली बनाया। इस दौरे ने अंतरराष्ट्रीय अतिथियों को कॉलेज के जीवंत शैक्षणिक माहौल और सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने और अनुभव करने का अनूठा अवसर दिया।

छात्रों को संबोधित करते हुए शरनदीप सहोता, मिस कोवेंट्री और मिस इंग्लैंड फाइनलिस्ट तथा बोपा की यूथ एंगेजमेंट कमिटी की अध्यक्ष, ने युवाओं की सशक्त भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा अपनी आवाज और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से समाज में समावेशिता, समानता और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कार्यक्रम में डॉ. राकेश सचदेवा, बोपा के अध्यक्ष, ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और युवा संस्थानों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इस सहयोग से न केवल सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है, बल्कि युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित कर उन्हें सकारात्मक और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

कार्यक्रम में मिस शार्लेट ग्रांट, मिस इंग्लैंड वर्ल्ड 2024-26 ने छात्रों को अपने अनुभव साझा करके प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग सामाजिक मुद्दों को बढ़ावा देने और युवाओं को परिवर्तन के प्रचारक बनाने के लिए किया। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता रही मिस ग्रेस रिचर्डसन, मिस इंग्लैंड 2025-26 का संबोधन। उन्होंने युवाओं को अपने असीमित संभावनाओं में विश्वास रखने और शिक्षा, स्वयंसेवा और नेतृत्व के माध्यम से एक संवेदनशील और समावेशी दुनिया बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में देविंदर प्रसाद, जेपी, एमजेएफ, ब्रिटिश संगठन बोपा (ब्रिटिश आर्गेनाइजेशन फॉर पीपल आफ एशियन आरिजिन) के महासचिव, ने प्रवासी संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ऐसे संगठन यूके और भारत के समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही, उन्होंने युवाओं को सामाजिक और मानवतावादी पहलों में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का एक विशेष क्षण था किताबघर की छात्राओं के साथ संवाद और समूह फोटो का अवसर। यह कम्युनिटी लर्निंग सेंटर युवसत्ता द्वारा संचालित किया जाता है और इसका उद्देश्य बापुधाम कॉलोनी, सेक्टर-26 की हाशिए पर रहने वाली लड़कियों को शिक्षा और मेंटरशिप के माध्यम से सशक्त बनाना है। इस अवसर पर प्रमोद शर्मा, संस्थापक युवसत्ता, ने युवाओं के लिए कार्यक्रम और अवसर बनाने में और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के योगदान की सराहना की।